[Shri Valampuri John]

frastructure for the establishment of National Institute at Palayamkottai, Tamil Nadu is readily available.

It is a matter of grave concern that the Government of India does not show even 1/10th of the interest which the Western countries evince in the development of Siddha system as an alternative medicine in their respective countries.

Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. M. G. Ramachandran has already allotted 100 acres of land in Palayamkottai for the establishment of National Institute of Siddha.

I would like to request the hon. Health Minister to evince keen interest in the development of this unique system of medicine Siddha at his earliest possible opportunity.

THE MERCHANT SHIPPING (SECOND Amendment) Bill, 1987

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Yogendra Makwana.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Madam Deputy Chairman with kind permission I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Madam, I introduce the Bill.

HOMAGE TO HIROSHIMA VICTIMS

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the hon. Members are aware, today is the forty-second anniversary of the dropping of the first ever atomic bomb on innocent people of Hiroshima killing, maiming and disabling lakhs of people. That was a dastardly and heinous crime perpetrated on humanity The years that have gone by have witnessed development of nuclear weapons thousands of times more powerful than the atomic bomb that fell on Hiroshima. We reiterate the demand of all human kind for immediate stoppage of the nuclear race and for dismantling the existing nuclear stockpiles.

I request the Members to rise on their places and observe silence as a mark of respect to the victims of the atomic holocaust.

(Hon. Members then stood in silence for one minute).

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

THE DEPUTY CHAIRMAN: Short Duration Discussion, Shri Ram Chandra Vikal.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Haryana): Madam, I want to make a submission. Through my submission, I want to express my deep anguish and protest.**

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it about?

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Because of the discriminatory treatment meted out to Members by these people.. ..I am telling you, Madam, You please hear me.

THE DEPUUTY CHAIRMAN: Yes, I am listening to you.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैंने 4 तारीख को यहां हाउस के अन्दर एक सबमिशन दी थी। मैडम, उस सबमिशन के जरिये मैंने अपने पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर और गवर्नमेंट की यह अर्ज की थी कि चूंकि अपोजीशन यहां पर मौजूद नहीं है इसलिए हाउस को दो दिन के लिए एडजर्न कर दिया जाए। इसमें बहुत सी न्यूज ऐसी है। I am expressing it with some agitation because it concerns my own self.

**Not recorded.

उपसभापति : सुनिये, आप ऐसा कीजिये आप चेम्बर में आ कर के डिसकस कर लीजिये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं तो यहां पर सबमिशन कर रहा हूं इसलिए अन्दर चेम्बर में आने की क्या बात है। यह कोई चेम्बर में बताने की बात थोड़े ही है **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप चेयर की परमिशन लेकर ही बोल सकते हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं परमिशन लेकर बोल रहा हूं।

उप सभापति : आपकी बात मुझे बहुत लम्बी दिखायी देती है। अगर कोई आपकी ग्रिवेंस है...

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आपके पास एजेंडा हो क्या है। जल्दी क्या है मैडम।

उपसभापति : जल्दी नहीं है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आप दो मिनट वेट कर लीजिये **(व्यवधान)** कहते हैं कि एजेंडा लाएं कहां से। एजेंडा तो आज का कालिंग अटेंशन मोशन का था वह लिया होता **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप मेरी बात सुनिये जरा आपको जो भी कहना है उसकी दूसरी साइड क्या है मुझे अभी पता नहीं है इसलिए मैं इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं दे सकती हूं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं आपसे डिसीजन नहीं मांग रहा हूं।

उपसभापति : आपको नहीं मांगना है तो फिर रेज़ क्यों कर रहे हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आप मेरी बात सुन लीजिए।

उपसभापति : आपको जो कुछ भी कहना हो मेरे पास चेम्बर में आकर डिसकस कर लीजिये। यह कोई तरीका नहीं है। इस प्रकार से हाउस नहीं चलता है कि आपकी जब भी जी में आए उठकर अपनी बात कहने लगे **(व्यवधान)**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैडम, मैंने तो आज तक आपसे कोई बात नहीं की। आप मेरे ऊपर यानी इस चीज़ के लिए ऐसे न कहें **(व्यवधान)**

उपसभापति : मैं यह कह रही हूं कि आपको जो भी कहना हो जो ग्रिवेंस हो तकलीफ हो वह आप मुझे जरूर बता सकते हैं। यह बताने की जगह नहीं है। आप चेम्बर में आइये मुझे बताइये मैं जरूर देखूंगी I will look into it and try to solve your problem. That is not the question.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से आप अनायड फील कर रही है।

उपसभापति : मैं अनायड फील नहीं कर रही हूं।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: This is the first time I am making a submission, that too with your permission.

उपसभापति : यह कोई प्रोसीजर नहीं है, यह कोई तरीका नहीं है **(व्यवधान)** मैंने आपसे बताया है कि यह कोई प्रोसीजर नहीं है, तरीका नहीं है। मैंने सोचा कि आपकी कोई टैम्पोरेरी चीज़ है जो आप बता रहे हैं। आपने कुछ ** कहा और पहले मुझे भी पता चलना चाहिये कि दूसरी साइड क्या है। आप कुछ कहेंगे तो मुझे ** भी पूछना पड़ेगा कि हुआ है। इसलिए मैं जब तक दूसरी बात नहीं जान लेती तब तक मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं।

**Not recorded.

[उपसभापति]

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं पूछने की बात नहीं करता न जवाब देने की बात करता हूं। मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सुन लीजिये * * * * मैं 20 सालों से दोनों हाउसेज के चक्कर लगा रहा हूं। कभी ** यह समझता हूं कि टी०वी० के ऊपर मेरा नाम आने से मैं यहां इस हाउस के अन्दर आता हूं। मैं तो यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यह मेरी स्पीच जो हम यहां करते हैं उसको रिकार्ड न करें। This should not be recorded. मैं यह अर्ज कर रहा था कि तीन तारीख को कलमाडी साहब ने खड़े होकर कह दिया क्योंकि अपोजीशन के मैम्बर्स नहीं आए उनका टी०ए०डी०ए० बन्द कर दिया जाए। The news was flashed on TV. Did it add to the dignity of the House? हम इस किस्म की सबमिशन करते हैं तो That is a discriminatory treatment. I lodge a strong protest against it. You may take notice of it or not. हम लोकसभा के अन्दर या स्टेट लेजिस्लेचर के अन्दर... (व्यवधान)

उपसभापति : यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान) आप गलत तरीका अख्तियार कर रहे हैं। आपको जो बात कहनी थी (व्यवधान)

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : इतनी अनइम्पोर्टेंट चीजें फलैश करते हैं जो हमारे ब्यूज को रिफलेक्ट करती है कि उनको बंद कर दिया जाए... (व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: This will not go record.

12 Noon

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा को आरंभ करने का अवसर दिया। आज सारे देश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में आ चुका है। उसके भयावह परिणामों की वजह से इस देश का किसान और किसानों से संबंधित मजदूर आज बहुत दयनीय दशा में पहुंच गये हैं। उपसभापति महोदया, यह विषय ऐसा है कि इस में हमारे विरोधी दलों को भी यहां पर होना चाहिये था और उन्हें उसमें भाग लेना चाहिये था। यह भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषमों पर हमारे विरोधी भाई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सूखा और अकाल देश में पड़ा है उसकी वजह से से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त यहां इस सदी का पहला अकाल कहा जा रहा है यानी 100 साल पहले भी इतने दिनों तक मानसून अगस्त के महीने तक न पहुंचा हो ऐसा इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा है। जहां तक देश के ऐसे भागों का सवाल है मैंने और सभी ने देखा है अखबारों में भी समाचार आए हैं, कुछ इलाकों में मैं स्वयं भी गया हूं चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यू०पी० हो, कश्मीर हो, बिहार हो, सब जगह अकाल की स्थिति है। बिहार में जहां एक तरफ बाढ़ आ रही है वहां बिहार के अंदर कुछ ऐसे जिले है, जो सूखे से ग्रसित हैं जैसे समस्तीपुर जिला है। कई जिले ऐसे हैं बिहार में जो सूखा ग्रस्त हैं। इस तरफ से देश का बहुत बड़ा भू भाग आज सूखे की चपेट में आ चुका है और खरीफ की फसल का समय तो जा चुका है रबी की फसल के लिए भी भविष्य में कोई आशा किसानों को नजर नहीं आती है। जहां तक फसल का सवाल है वह तो समाप्त हो चुकी है। जो सब से बड़ा भयावह दृश्य आज किसानों के सामने है वह यह है कि मवेशियों की मौतें हो चुकी हैं। आज चारे और पानी के अभाव में लाखों-लाख मवेशी गांव से बाहर जा चुके हैं मर चुके हैं और उनकी देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। न चारा है, न पानी है मनुष्यों के लिए परेशानियों के साथ साथ पशुओं पर भयानक अकाल का प्रभाव पड़ा है वह किसानों की आर्थिक स्थिति को एक तरफ से समाप्त करने वाला है। मवेशी भी किसानों की खेती में एक

**Not recorded.

तरफ से सहायक होते हैं उसकी आर्थिक स्थिति में सहायक होते हैं। उपसभापति महोदया, हमारे गांवों में यह कहावत कि मनुष्य जब मरता है तो लोग बैठ कर रोते हैं, जब किसान के मवेशी मरते हैं तो उसे खड़े होकर के रोना पड़ता है। आज मवेशी और फसल की वजह से किसान बहुत बड़ी भयावह स्थिय में पहुंच चुका है। मैं परसों नागपुर में था। वहां मुझे यह मालूम हुआ कि गुजरात के लिए कुछ चारे का इन्तजाम महाराष्ट्र की तरफ से हो रहा है लेकिन जब महाराष्ट्र में इस अकाल की विभीषिका का सवाल आया वहां के लोगों ने तथा सरकार ने भी यह सोचा कि पहले हम अपनी भूख भगाएं। इसलिये गुजरात को जाने वाला चारा रोक दिया गया। उसके बावजूद भी वहां पर चारे का अभाव है। जिन राज्यों में वर्षा का अभाव है वहां चारे का अभाव है, पानी का भी अभाव है। यों तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कमेटी में सुना है, और आशा है कि उस कमेटी का कार्य शीघ्र चालू होगा। उस में कृषि मंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री और शायद सिंचाई मंत्री भी शामिल हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है हो सकता है और भी कोई मंत्री होंगे। यह जो समिति बनी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जरूर सारे राज्यों मे संपर्क करेगी वहां की सारी कठिनाइयों को जानकर राज्यों और के केन्द्रीय सरकार में आपस में सामंजस्य कर के शीघ्र ही हमारी इन कठिनाइयों को मजदरों की जो भयावह स्थिति है उस पर पूर्ण सहायता पहुंचाएगी कुछसहायता कार्य हुए भी हैं स में कोई दो राय नहीं है मेरी जानकारी में भी है लेकिन यह शिकायतें भी हम को मालूम हुई है कि सहायता कार्य में सहायता हमारे कुछ अधिकारी समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सहायता कार्य नहीं पहुंचाते और खाली पहुंचने में तो देरी होती ही है लेकिन उसमें कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मौजूद हैं। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी पर मुसीबत आती है तो मानवता के नाते तो उससे साथ हमदर्दी होनी चाहिए, मगर यहां पर हमदर्दी के बजाय व्यापारी चीजों के भाव बढ़ा देते हैं। चारा लीजिए, खाने की चीजें लीजिए, अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में और राज्यों में व्यापारियों के ज्यादा पैसे बन रहे हैं और मजबूरी में लोगों को सामान महंगा खरीदना पड़ता है, उनको दाम ज्यादा देने पड़ते हैं। यह कई तरह की ऐसी मार है जो कि आज किसानों पर पड़ रही है फसलों के अलावा जो व्यापारियों की वजह से मंहगाई हुई है उससे भी वे त्रस्त हुए हैं, चारे की मंहगाई से भी त्रस्त हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतय्या) पीठासीन हुए।

कृषि मंत्री जी यहां सौभाग्य से मौजूद हैं, मैं उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो आपकी समिति बनी है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत राज्यों से संपर्क करके और सारी जानकारी प्राप्त करके जो सहायता केन्द्र पहुंचा सकता है वह जल्द से जल्द पहुंचाये और साथ ही यह भी देखे कि गरीबों तक सहायता पहुंचने में कोई कठिनाई तो नहीं है। इस पर तुरन्त युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए और सहायता पहुंचाने में अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें हैं तो ऐसे कर्मचारियों को तुरंत दंडित कराना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो जाए कि ऐसे संकटकाल में हमें अपने खराब इरादों को पब्लिक के साथ नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज जैसे जो चारे का अभाव है इसके लिए मैं नहीं चाहता हूं कि वनों को उजाड़ा जाए लेकिन उसे चारागाह के तौर पर वन विभाग को तुरंत खुलवा देना चाहिए इस देख-रेख के साथ कि वहां पेड़ों को कोई हानि नहीं हो। चारागाह के तौर पर मवेशियों के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। वनों में पुरानी या नई घास है उसको किसानों को इजाजत दी जाए तभी चारे के मामले में उनकी थोड़ी बहुत सहायता हो सकती है। हमारे चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे गुजरात का इन सभी राज्यों में और

[श्री रामचन्द्र विकल]

यू०पी० के चीफ मिनिस्टर ने कल ही मांग की है और केन्द्रीय सरकार से सौ करोड़ रुपया मांगा है केरल के चीफ मिनिस्टर ने भी मांग की है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के सब मंत्रियों, जिन राज्यों में सूखा है वहां के सभी मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र से सहायता मांगी है। अब केन्द्र को सहायता करने में देरी नहीं करनी चाहिये और राज्य सरकारों को भी आदेश दे कि वे अपनी तरफ से भी कुछ बजट अकाल राहत के लिए निकालें ताकि गरीबों तक सहायता पहुंच सके। तीसरा पीने के पानी का संकट मनुष्यों के लिए भी भयावह हो गया है खाली पशुओं तक ही सीमित नहीं रहा है इस अकाल के कारण पीने के पानी की समस्या भी बहुत कुछ भयावह हो गई है । इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था में भी सुधार किया जाए। जमीन पर पानी का लैवल बहुत नीचे जा चुका है इस प्रकार हमारे ट्यूबवैल फेल हो चुके हैं यदि कहीं हेडपंप लगाकर पानी की व्यवस्था की जा सके तो वह व्यवस्था भी तुरन्त की जाए यदि बाहर से पानी लाकर व्यवस्था करनी पड़े तो वह भी करनी चाहिए चाहे ट्रकों से हो, चाहे रेल-गाड़ियों से हो तो इसकी व्यवस्था के लिए हमारे केन्द्र और राज्य सरकारों को मिल कर काम करना चाहिये जहां तक बीमारियों का सवाल है मनुष्यों में और पशुओं में भी बीमारियों की शुरुआत इस अकाल की वजह से हो चुकी है। इस अकाल की वजह से चाहे मवेशियों की बीमारियां हो चाहे मनुष्यों की बीमारियां हो उनकी बीमारियों के इलाज में भी तत्परता बरती जानी चाहिए ।

मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी का केन्द्र और राज्य सरकारों का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस भयावह अकाल के समय में कितनी अधिक से अधिक सहायता किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की हो सके वह करनी चाहिए चाहे पीने के पानी की समस्य हो, चाहे मवेशियों के इलाज की समस्या हो, चाहे मनुष्यों के इलाज की समस्या हो, चाहे उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने का सवाल हो, और चाहे जिस तरह की भी सहायता हो उनको तुरन्त दी जाये साथ ही किसानों पर जो पुराने बकाया पड़े हैं चाहे बैंकों के ऋण हों, चाहे आबपाशी के बिल हों, चाहे बिजली के बिल हों और चाहे दूसरे डयूज हों वे इस वक्त समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि आज किसान इस हालत में नहीं है कि वह कर्जा चुका सके।

इन शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी का देश के जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं अकाल पीडित क्षेत्र हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आशा करूंगा कि जिस रूप में भी संभव हो सके सहायता पहुंचायी जाये। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य भी होना चाहिए केन्द्र की सहायता कहां पहुंच रही है उसका उपयोग कैसे हो यह देखना चाहिए । केन्द्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य के लिए कुछ ऐसी कमेटियां बना दी जाएं ताकि केन्द्र राज्य सरकार के विचार विमर्श से तुरन्त कार्य-वाही चालू कर सके। जहां केन्द्र की समिति बनी है वहां राज्य सरकारों के साथ ऐसी कमेटियां होनी चाहिए जो केन्द्र राज्य सरकारों का आपस में सामंजस्य कर के सहायता कार्य जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें ।

मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि कृषि मंत्रालय अभावग्रस्त क्षेत्रों के किसानों व मजदूरों की तुरन्त सहायता करेगी और इस मुसीबत में मदद कर सकेगी ।

श्री धर्मचन्द प्रशांत (जम्मू और काश्मीर) उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश को एक महान संकट का सामना करना पड़ रहा है वह संकट है सूखे की स्थिति बड़ी गंभीर है सूखे का मतलब अकाल है होता है सूखे के बाद अकाल पड़ता है। इससे पहले भी देश में कई अकाल पड़ चुके हैं जिनके कारण हजारों लोग मृत्यु की गोद में चले गए। वर्ष 1941-42 में बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें लाखों आदमी अकालग्रस्त हुए, मर गए और इतना भीषण अकाल उससे पहले कभी नहीं पड़ा था। 120 वर्ष पूर्व हमारे काश्मीर में भी एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था। हजारों

आदमी मर गए और हजारों वहां से भागकर दूसरे राज्यों में चले गए। इस समय देश में सूखा पड़ रहा है क्योंकि बारिशें नहीं हुई। इससे पहले इतनी बारिशें हुई कि उनसे भी हमारी अनाज की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां कि लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहें हैं। सरकार को चिंता है और होनी चाहिए और जरूरी है कि इसके लिए मुनासिब कदम उठाए जाएं ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोग इस संकट से बच सकें यह संकट मामूली नहीं है। यह बतला रहा है कि आने वाले दिनों में देश में कहां तक अकाल पड़ेगा और लोगों पर क्या बीतेगी, अगर इस समय इसके लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किये जा सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अकाल तो दूसरे राज्यों में भी है और उनके साथ मिलकर जाइंट कमेटीज बनायी जाएं। केन्द्र और राज्य सरकार की ये जो कमेटीज हों, ये युद्ध स्तर पर बनायी जाएं और इनके कार्य में कोई ढील न हो। इस सूखे के कारण वे लोग जिनको पानी नहीं मिल रहा है और हमारे पशु जो चारे के अभाव में मर रहें हैं, उनके लिए प्रबंध किए जाएं। इस कार्य में ढील न की जाए। अगर इस कार्य में ढील हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this august House to a very important phenomenon at present prevailing in the country. Drought or scarcity of water has become a regular phenomenon for the last three years and all the forecasts and the observatory reports have been belied. What is happening is happening for the worst and the condition throughout the country has gone from bad to worse. Even on mountains there is no grass. There is no grass or grazing place. The cattle cannot graze. The climatic conditions have gone to the extreme. Heat has increased. Even the animals are unable to bear the heat. The heat that we are experiencing in Delhi is being experienced all over the country. The trouble of heat is there all over the country excepting some parts which have received a little rain.

Mr. Vice-Chairman, extreme climatic conditions have resulted in epidemics. Epidemics like cholera, fever, diarrhoea, have already started in rural areas and there are no proper medical facilities available there. Only first aid is provided to meet the situation. The first-aid measures are only temporary. They are not satisfactory and they are not also in consonance with the requirements of the rural people. Rural people are facing a lot of troubles. I would only mention one instance. Water is being supplied to villages with the help of tankers, but if there is a failure or disorder in the tanker, there is no alternative and the water does not reach the place. There is no arrangement for standby tankers. Therefore, in order to face these calamities, I would suggest two important things.

Firstly, the river water disputes should be settled with irrevocable verdicts by the Government of India. Unless the river water disputes are settled, creating of first-aid reliefs would not suffice.

Secondly, the big water canals may be inter-linked by inter-linking system so that the water that is wasted or that goes to the sea is converted and made available to various parts of the country. This water can be used for drinking purposes or for agriculture.

Thirdly, if this is done, naturally, the hydro electric plants would come into existence and the power supply problem would be solved. Therefore, I have to make all these suggestions.

Now, Sir, coming to the scarcity areas, the scarcity areas cover not only the rural areas but most parts of the country. It concerns us as to what meaure you have taken to remove these scarcity conditions. Secondly, it refers to the expenditure that is required to remove troubles in the scarcity areas. Also, it is concerned with the expenditure that is required from the Central Government and the new drought problems that are constantly recurring may be faced and for this purpose, there are long term and short term schemes which are to be made with efficient people involved in it. Otherwise, what hap-

[Shri Shankarrao Narayanrao Deshmukh]

pens? There is a saying, "The hedge has eaten away the crops." I repeat, the hedge has eaten away the crops and the experience has shown and instances are not uncommon where the money given for the drought purpose has gone to places which most of you know and the country knows. Therefore, I suggest that there should be a Vigilance group created by the Central Government and the State Governments to look into these bad circumstances.

Now, I will come to the State of Maharashtra. Sir, the assistance that was sought by the Maharashtra State during 1986-87 and 1987-88 was to the extent of Rs. 494.69 crores. This included Plan and Non-Plan expenditure both and as against that, the Centre Study Team headed by Mr. J. N. Arora, Joint Secretary, Ministry of Agriculture, Delhi had visited the scarcity affected areas in the State during the period from December 9th to 12th, 1986. Thereafter, the Government of India, vide its letter dated 16.2.87 had approved a ceiling for expenditure to the tune of Rs. 37.75 crores. See the difference. Maharashtra State is well known for so many things, both as agriculture producing area as well as drought strikenin area. The demand was for Rs. 494.69 crores and as against that, the ceiling was imposed to spend only to the extent of Rs. 37.75 crores, but this excludes the scarcity relief work, fodder supply, medical care and public health and nutrition programmes etc. This the Government meets from its own resources. The Government of Maharashtra finding this amount very insufficient had a supplementary memorandum for emergent relief measures had been prepared and sent to the Government of India on 23rd May, 1987 whereby Central assistance of Rs. 290.95 crores had been demanded. Again, the Government of Maharashtra gave the full assessment, full details, as required by the Government of India. The demand was Rs. 290.95 crores. Item-wise, this included all the Plan and Non-Plan expenditure for 1986-87. And thereafter what has happened? Sir, in pursuance of the aforementioned supplementary memorandum on scarcity conditions, the Central Study Team headed by the Joint Secretary, Ministry of Agriculture, New Delhi—I am very happy that the hon. Minister for Agriculture is present in the House—visited the scarcity affected areas of the State during the period, very recently, from 3.5.1987 to 6.5.1987, only in May, not long back. With reference to the supplementary memorandum, the Government of India, vide its letter dated 26.6.1987, has sanctioned Central assistance of Rs. 18.72 crores. Sir, I am quoting these figures not to dazzle the eyes of the House. I know statistics always dazzle the eyes. They just sway the scales one way or the other. I am quoting these figures in context with the monies that are being drained up by the sophisticated, industrialised companies just asking to write off loans. What a disparity ! What is the justification for it ? Is there any justification not to grant relief to the rural areas for the legal necessities of life of people and their cattle which are the productive classes ? Here, when the demand is made for so much of amount for sustaining the lives of people, you say, "All right, you get so much." What is the justification for it? Today, only in the morning, I have brought to the notice of this august House that Rs. 9 crores are swindled by 22 or so manufacturers. Nine crores! And here, you give us ten crores. What is the justification for this distribution. I think it is nothing but misunderstanding, miscalculation and misjudgement of the rural poor. Sir, I shall go a step further. I have brought all the figures to you. It is seen from the sanction order of the Government of India dated 26.6.1987 that the additional Central assistance had been sanctioned for the year 1986-87. This Central assistance for drinking water supply was demanded on the basis—this is more important—of the number of villages accepted by the Government of India and the statement of the actual expenditure based on the same was given.

Lastly, it is very surprising that the Central assistance was sanctioned after three months from the date of submission of

the memorandum and the same was sanctioned just five days before the expiry of the period to utilise the same. Therefore, I say, the hedge will eat away the crop. You are sanctioning it just five days before the expiry period? Can the State straightway make the expenditure? If you ask them, they will only say, yes, we have spent the money and the officers are prepared to fill up the registers. After you have sanctioned the money, I think the paper that will have to move through the Treasury will take at least a month. How can they adjust it? It would be seen that the Government had sanctioned Central assistance only to the extent of Rs. 56.47 crores to the Government of Maharashtra for the years 1986-87 and 1987-88. This is the picture, this is the comparative picture, of rural India. I say it again, as I had already said in my previous speeches, if crores of rupees could be eaten away or could be written off by Government at their sweet will and pleasure for the sophisticated class of industrialists and other companies, why neglect rural India? What is the justification? It is reported recently that the honourable Prime Minister has constituted a committee for this purpose. I submit that every State Chief Minister or in his place his Finance Minister may be included in that committee so that he may be able to give a true picture of his State.

Lastly, I suggest that all these first aid measures should be converted into permanent measures; otherwise, you cannot meet this phenomenon which is occurring off and on in this country. Thank you.

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसका देश पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ने जा रहा है उस पर जो चर्चा हो रही है उसमें रुचि का अभाव प्रतीत हो रहा है । हमारे किसान भाइयों की समस्याओं को टेक-अप करने वाले और इस बहस को प्रारम्भ करने वाले हमारे मित्र श्री राम चन्द्र विकल ने एक बड़ी कमजोर वकालात शुरू की है। इससे यह तथ्य प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों की रुचि कम है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सूखे का सवाल महज कृषि मंत्रालय से संबंधित नहीं है । इसका संबंध तो कई मंत्रालयों से है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर इससे संबंधित मंत्रालय यदि गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो देश के सामने जो भयावह परिस्थितियां भविष्य में आने वाली हैं उसका समाधान हमारे लिये अत्यन्त कठिन होगा । महोदय बाढ़ और सूखे के बीच एक बड़ा मौलिक अंतर होता है । जब बाढ़ आती है तो फसल बरबाद होती है, घर गिर जाते हैं, कुछ लोग बेघर हो जाते हैं, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है । मगर जैसे ही बाढ़ हटती है वैसे ही भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाती है, पानी के हटते ही जमीन की जो जनन शक्ति है उसमें वृद्धि होती है और उसके बाद की जो फसलें होती हैं वे अच्छी होती हैं । लेकिन सूखे में विरोधी, विपरीत परिस्थितियां होती हैं। जब सूखा पड़ता है और जो इस साल का सूखा है इसके संबंध में हमारे प्रारम्भकर्ता ने सही कहा कि इस शताब्दी में इससे खतरनाक सूखा कभी नहीं पड़ा।

मैंने भी अपने इस काफी समय के जीवन में कई सूखे देखे किन्तु ऐसा सूखा मुझे अब तक दिखाई नहीं पड़ा । मैं उसका एक मूल रूप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जैसा अभी कहा गया 7-8 राज्यों में पीने के पानी तक का अभाव है मगर पानी जो भूमि की शक्ति है जो उसकी जनन की शक्ति है, इस सूखे ने वह भी समाप्त कर दी है पानी का धरातल इतनी तेजी से नीचे घट रहा है कि ऊपर की नमी को समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा । मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि केवल खरीफ की फसल ही नहीं जा रही है बल्कि आगे आने वाली रबी की फसल भी पैदा नहीं होगी । मुझे आश्चर्य होता है जब लोग ऐसे सूखे में सुझाव देते हैं कि बिजली का संकट यदि हल कर लिया जाये और

[श्री वीर भद्र प्रताप सिंह]

नहरों में पानी दे दिया जाये तो खेती हो जायेगी। मैं समझता हूं उन्हें खेती के बारे में अनुभव नहीं है शायद वे किसान नहीं हैं अगर वे किसान थे तो भी वे भूल गये हैं। शायद वे गांव में नहीं जाते हैं खेतों में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं तो स्वतः गांव में जाता हूं, खेतों में जाता हूं इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि नहर और ट्यूबवेल ही नहीं यदि जमीन में नमी रही, शुरू की बरसात हुई तो जाती हुई फसल को बचाने का वह काम करती है। मैं अभी कल इधर गया था बुलन्दशहर के कुछ इलाकों में, जो विकल जी का इलाका है इनके जिले से भी गुजरा और मैंने देखा कि घास है, वह सूख रही है, जो बाजरे की फसल है वह सूख रही है और सबसे बड़ा संकट यह है कि जो गरीबों के खाने का अन्न धान से पहले पैदा कर लेते थे वह बिल्कुल बोया ही नहीं गया और जो गरीब लोग खाते थे, उसका अब अभाव हो गया है। यह सही है कि जानवरों के चारे का अभाव हो गया क्योंकि जो चारा खेत में किसी तरह बो दिया जाता है नहर के पानी से या ट्यूबवैल के पानी से, अब वह भी सूख चला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि मवेशी क्या खाएंगे ? तो खेती का संबंध खेतीहर से है' किसान से है, मजदूर से है, उसका जानवरों से है। खेती में केवल बैल महत्वपूर्ण नहीं होता है, खेती में गाय और भैंस भी महत्वपूर्ण होते हैं। खेती में केवल ट्रैक्टर हर काम नहीं करता है। अगर किसी को गलत फहमी हो कि इस मुल्क में मैकेनिज्म फार्मिंग से ट्रैक्टर से खेती हो सकती है तो मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि बहुत सा काम खेती का ट्रैक्टर करता है लेकिन ट्रैक्टर के बाद भी बैल की जरूरत होती है गाय और भैंस की जरूरत होती है, उसके गोबर की जरूरत होती है। खेती एक सामूहिक बहुत सी चीजों का सम्मिश्रण है। मगर मैं यह देख रहा हूं कि सूखे से हर चीज टूट रही है, कोई चीज ऐसी नहीं है, जो उपलब्ध होती दिखाई पड़ रही है। फिर हमारे जानवर खाएंगे क्या ? यह जो चारा सूख रहा है, जिसको हम नहर और ट्यूबवेल के पानी से जिंदा नहीं रख सकते हैं, तो फिर वह खाएगा क्या ?

फिर अब आइए, किसान की उपज और उसमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों का हिस्सा, जो उनकी भुगतान का है, कितना बड़ा अनएम्पलायमेंट मुल्क में फैलने जा रहा है, कितनी बड़ी बेरोजगारी देश में फैलने जा रही है और जो आने वाला संकट है वह इससे बड़ा है। मैं आपको फिर से सचेत करता हूं कि केवल कृषि-मंत्रालय को ही इस तरह सोचने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जितने संबंद्ध मंत्रालय हैं, सबको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अगर शुरू में बरसात का पानी नहीं बरसा, अगर धरती की नमी गायब नहीं हुई, यदि धरती की जो जनन शक्ति है, वह इस वक्त पैदा नहीं हुई तो आगे आने वाली रबी की फसल इस मुल्क में नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का संकट हमारे देश के आठ राज्यों में उपस्थित है। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा जहां पर कि पीने के पानी के जो हैंड पम्प लगाए जाते हैं वे सब बेकार साबित हो रहे हैं क्योंकि सूखे ने सबके पानी के धरातल को नीचे कर दिया है। अब प्रश्न है कि खेती की पैदावार होगी नहीं, धान की फसल हम उगा नहीं सकते हैं और इस गलतफहमी में मत रहिए कि रबी में बरसात नहीं होती तो फिर इससे क्या संबंध है। बरसात रबी में इस देश में अवश्य नहीं होती है लेकिन रबी के लिए जो नमी आवश्यक है जमीन में जो पानी का धरातल आवश्यक है, जब बरसात पर बरसात होती है तो पानी का धरातल जो ऊपर उठने लगता है वह ऊपर की सतह को नमी में परिवर्तित करके रखता है और रबी के वक्त थोड़ी सी सिंचाई में, ट्यूबवेल रहट की सिंचाई में खेती हो जाया करती है लेकिन आने वाली संभावना बड़ी खतरनाक है। मैं इसलिए सरकार से

निवेदन करूंगा कि केवल कृषि मंत्रालय से इसको सम्बद्ध न समझें, तमाम मंत्रालय इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और सोचें । ऐसा कभी नहीं हुआ था । मेरी काफी लम्बी जिंदगी है कि पूरी अगस्त के इस समय तक जो सामान्य पहली वर्षा होती है कहीं वह भी नहीं हुई है । कहीं कहीं तो 2 - 4 दिन बरसात हुई फिर गायब हो गयी । इसका परिणाम यह होने जा रहा है कि अकाल की परिस्थिति इस बड़े भारी जनसंख्या वाले देश में पैदा होने जा रही है । इसका मुकाबला हम किस प्रकार कर सकेंगे ?

अभी खाद्य मंत्रालय ने घोषणा की कि हम गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलेंगे । क्या मैं उनसे बहुत निवेदन से पूछूं कि शहरों में जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं और उनमें जो जरूरी आवश्यक चीजें जाती हैं जिनकी कमी है और जो बाजार में मंहगी हैं, क्या ठीक दाम पर उपभोक्ताओं को मिल जाती हैं ? प्रश्न यह नहीं है कि आप गांव में देहातों में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें खोल देंगे, प्रश्न यह है कि गरीब उपभोक्ताओं को वे चीजें किस प्रकार उपलब्ध हो जायेंगी ? प्रश्न यह है कि वह सामान ब्लैक मारकेट में जाने से आप कैसे रोक देंगे । किसी माननीय सदस्य ने बताया कि महाराष्ट्र में दो कमेटियां हैं जस्ट लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज जो कंज्यूमर्स के, उपभोक्ता के इंटरेस्ट को वाच करती है और वितर कराती है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आपकी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनमें जो सामान उपलब्ध होता है और वह सचमुच जिनको जरूरी है उन उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जो खाद्य विभाग है उसको कमर कसकर अपनी योजनाओं को लागू करना चाहिए वरना उससे जिस गरीब को सस्ता गल्ला देना चाहते हैं या सस्ता सामान देना चाहते हैं उसे उपलब्ध नहीं होगा ।

एक बात सरकार से और कहकर उपसभाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । यह संकट का वक्त ऐसा है कि जब हमें कमर कस कर फिजल खर्ची को रोकना चाहिए । विकास जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा और उत्तर प्रदेश ने सो करोड़ मांगे हैं मैं कहता हूं कि क्या आवश्यकता थी जिले बनाने की हमारे मुख्य मंत्री जी को, बड़ी खुशी है कि उन्होंने तीन जिले बना दिये लेकिन हर जिले में सौ करोड़ रुपये का खर्च है । तो सौ करोड़ का फेडरल बर्डन उत्तर प्रदेश रोक सकता था और फिर केन्द्र से सौ करोड़ रुपये का मांग करने की आवश्यकता नहीं थी । एक तरफ आप लालच पैदा करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तीन जगह जिले बनायेंगे, तीन सौ करोड़ खर्च करेंगे और दूसरी तरफ जनता को राहत देने के लिए सौ करोड़ का अनुदान केन्द्र सरकार से मांगेंगे । मैं समझता हूं कि फिजूल खर्ची का इससे बड़ा उदाहरण समग्र राष्ट्र के आर्थिक जीवन में आया नहीं है । इसलिए हमें कठोर होकर यह वेस्टफुल एक्सपेंडीचर किसी रूप में हो इसको कहीं न कहीं रोकना चाहिए । पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जैसे राव साहब ने कहा है युद्ध स्तर पर, युद्ध से भी भयंकर संकट का समय है क्योंकि जिसमें कुछ बिगड़ता है, कुछ टूटता है, कुछ बर्बाद होता है, कुछ जल जाता है, लेकिन कृषि प्रधान देश के लिए यह हर वर्ष बार-बार कर युद्ध स्तर पर हर परिस्थितियों का मुकाबला नहीं किया तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस सरकार का सभी-सभी लुट जाएगा हम पता नहीं कब गये । अतः मेरा अनुरोध है कि अब तक जो मानसिकता है अब उसे परिवर्तन कर हमें दूसरा मानसिकता से, दूसरे स्तर पर हल करना चाहिए । धन्यवाद ।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan): Sir, it is distressing to find that a large area of the country is passing through severe drought this year. Owing to dry and warm air currents which started from the Caspian Sea in the U.S.S.R: towards India, our South_west monsoons have unfortunately been blocked and the result of that has been that there has been a failure of South-west monsoon which has affected crores of people,

[Shri Krishna Kumar Birla]

It has resulted in the destruction of crops and scarcity of water. It is estimated that out of 406 districts in the country, 256 districts or 62.5 per cent of the districts have been affected by this drought. This is the fourth consecutive year of drought and this drought is the worst that the country has seen in this century. In the villages, people have to walk long distances to get water from the wells because most of the wells have dried up. In the cities the position is no better. Rationing of water has been resorted to in a number of cities. About Rajasthan, I will speak a little more in depth a bit later.

Side by side, I woud like to mention that milions of workers are also going to be affected by this drought, if not directly certainly indirectly, because the demand is going to go down owing to drought. Unless the people have money, who will buy? Who will purchase the goods if people do not have money? In fact, the inventories have already started going up. The matter is even more serious because this is going to affect the Seventh Plan also. It is estimated that the cotton crop is going to go down by almost 30 per cent this year. The foograins production is likely to go down by about 15 lakh tonnes. Probably, the total production of food grains will be 140 million tonnes only this year. The sugarcane crop has started withering away in U.P.

As I have mentioned, Rajasthan is the worst affected area. Barring the one district of Bikaner, all the other districts of Rajasthan have been affected by drought and about 31,922 villages have been declared scarcity areas. There is shortage of drinking water. There is shortage of fodder. Wells have dried up. The kharif crop is expected to be affected by 75 per cent to 90 per cent. The rainfall is only about one-third on an average. The underground water level has gone down between 20 to 60 feet. There is migration of cattle to the neighbouring States and this has created law and order problem. This is the present situation. Side by side, minor irrigation works which can contribute a lot towards fighting such situations have been ignored. In spite of the fact that the Seventh Five Year Plan provides Rs. 6,522 crores for drinking water alone, the position is not satisfactory. What is required to be done is that in those States where handpumps could be successful they should be drilled without and delay. Side by side, tubewells should be drilled. First priority should be given to them.

Then, Sir, deforestation is a very important reason which has led the country to this unfortunate state. We have discussed the question of deforestation a number of times and yet we find the deforestation is taking place right and left and this is in spite of the fact that journalists have done a laudable thing by drawing the attention of the public to the harmful effects of deforestation which is going on in a number of areas including Garhwal, Mussorie, etc. etc. Then; Sir, I would like to make bold to say that deforestation is going on with the full knowledge and connivance of the authorities concerned. In my opinion it is a sin. What we have to do now is that we have to start a movement in the reverse direction, which means that we must start growing more and more trees and afforestation should be resorted to with the greatest amount of vigour.

Sir, it has been brought to my notice that fruit trees, once they are grown, require comparatively less water. In addition they provide nutritious food also for the people. I would, therefore, request the State Governments that they should encourage plantation of more and more fruit trees.

Sir, a word again regarding Rajasthan. This State, unfortunately is in no position to bear the burnt of successive crop failures. It has already

got pending bills which it has to pay to the tune of Rs. 82 crores. I would, therefore, very humbly appeal that the State Government of Rajasthan should be given 3½ lakh tonnes of food, all free, and that some cash assistance also should be given to the State for employing labour to fight drought so that they can get some money in their pockets with which to buy food. Drinking water is also required for which the State Government should be given assistance and fodder for cattle is also very necessary, so that the cattle wealth could be preserved.

Then, Sir side by side I would also appeal to the traders that there is an unfortunate possibility that owing to the drought condition the prices of foodgrains may go up. Trader brethren should know that this is the time when they should try to serve the people as much as possible by trying to keep the food prices at a reasonable level.

Sir, in these dark clouds it is some comfort to find that the Prime Minister has accepted the challenge and he has formed a sub-committee to fight the drought and he has taken it under his chairmanship. I hope, Sir, as a result of that he will be able to steer the country clear out of this crisis. It is a part of our duty, a part of the duty of the people, to strengthen his hands. I would appeal to all my business friends that they should try to strengthen the Prime Minister's hands by contributing to the Prime Minister's Relief Fund or to the Chief Minister's relief Fund or that they should organise relief work themselves wherever they find that there is a necessary of doing so. Thank you.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, we are discussing today the gravest problem that India is facing today. The House is rightly seized of this problem. I would not elaborate on the all-India situation because other friends have done the job. I would say that Gujarat, Rajasthan, Himachal, Punjab and Haryana have got the least rainfall in the country and in that, Gujarat situation is really tragic, because for the third consecutive year, Gujarat is facing scarcity.

In the previous two years we suffered immensely and this is the third year. Till the end of July, out of 19 districts of Gujarat, 16 districts are facing unprecedented drought. That means, more than three-fourths of Gujarat is facing scarcity condition. We have 184 talukas, and in 11 talukas there is no rain at all. In 88 talukas, the rainfall is just 15 per cent of the normal rainfall. In 47 talukas, it is just between 16 per cent and 25 per cent of the normal rainfall, and in only 38 talukas, there is a rainfall which is about 25 percent of the normal rainfall. Thus, we are facing a situation which is very grave.

If I could give some figures about the villages, the picture becomes much more horrible. Out of 18,000 villages, in 1985-86, about 13,000 villages were affected by scarcity. In 1986-87, about 12,000 villages were affected by scarcity. And this year, the rainfall is absolutely meagre and more than three-fourths of the State will be facing an unprecedented drought situation. We are keeping the Central Government continously informed about the situation in Gujarat.

Then, there is the question of food, fodder, drinking water and other relief works. I think the most important problem that has to be faced is that of drinking water. Last year, trucks and tankers were pressed into service to bring drinking water for the needy areas. Today also, hundreds of tankers and other vehicles are operating to carry water to needy areas. This time the situation is worse, because the subsoil water has gone down much deeper, and if it goes still deeper, the water could be rather saltish or brackish, and may not be consumed We do not have the surface water. In such a situation how would the State Government or the Central

[Shri Chimanbhai Mehta]

Government provide water? What you have to start thinking about is the reverse osmosis methodology and conservation of water. Some people are suggesting laying down of the pipeline from Narmada. Well, it is a capital intensive scheme but that is very much required. Then, there is also a suggestion of taking water from the mouth of Narmada through collapsible tankers and taking it on the sea-surface to the needy areas. All these possibilities have to be examined so that people have water to drink at least. At least,, people should be able to quench their thirst. The situation is dangerous and so alarming that it is feared that there may be a large-scale migration if water is not provided to the needy people.

1.00 P.M.

Then I would like to draw your attention to the prospects of food production; the loss in production rather. Our normal production of Kharif foodgrains is 32 lakh tonnes. This time, it is envisaged that the production loss will be to the tune of as much as 27 lakh tonnes. This means, only 5 lakh tonnes would be available. This is hardly 15 to 20 per cent. In the case of oilseeds, the production would almost be nil. The normal production is 14 lakh tonnes. This year, only 25,000 tonnes would be available. In the case of tobacco the entire crop is going to be a failure. Same is the case with cotton. Perhaps, there may be a negligible quantity in some districts. You can imagine from this how alarming the situation is.

Now, about relief works. Sir, this is the third successive drought year we are likely to face. This year, in the month of May, we had 14 lakh labourers on 10,000 relief works. Normally, the number should have come down considerably by this time and the relief works should have stopped. Because of the drought, however, at the moment, eight lakh labourers are working on 6,000 relief works. Of course we are hoping that rains may come. The picture is not absolutely dismal. We are not totally disappointed. We are hoping against hope. Therefore, the Central Government should come forward immediately with the required help. Of course, they are providing us wheat; this is given to the labourers as part of their wages. Rajasthan has also been supplied wheat. But our requirement is increasing. I would request that the Central Government should immediately give 1 lakh tonnes of wheat which is urgently required. I would also suggest that Gujarat should be treated in the same way as Rajasthan is which is given full subsidy on the wheat supplied. At present, we are being charged. This should be done away with We should be treated on par with Rajasthan. This is my request.

I have already mentioned about drinking water. A dangerous situation has arisen. (*Time bell rings*) I would add just one more point. Of course, this is a long-term idea. The Gujarat Government is working on the Narmada project. But finance is the main problem. Gujaratis in other parts of the world are prepared to help. Therefore, I would request that the Gujarat Government should be allowed to tap this source of non-resident Indians. The Gujarat Government should be allowed to float bonds or set up a capital fund. Since they are prepared to contribute there should be no hindrance because this is a national project, but it is a very important project for Gujarat and in this situation the importance of this is re-emphasized.

About the cattle relief, actually we require today per week 170 kg. of fodder but this is just not available. Compared to the requirement much less is availble. Therefore, I am afraid that thousands of cattle will perish and Gujarat will become the graveyard of this dying cattle population. We do not have grass or fodder in our State. Whatever was there during the last two years has already been exhausted. Therefore, other States have to come to our help immediately.

Whole thing has to be put on a war-footing. Other States like Andhra, Karnataka, Punjab, have been requested to help us. We also request the other States to come to help us in getting fooder required for our cattle.

About expenditure also, Central Government is helping or giving aid or putting a ceiling on our expenditure. That is woefully inadequate because the expenditure is much more and the Government is putting a ceiling, that won't come even to the 50 per cent of the expenditure we are incurring. And the State Government cannot bear this burden. This is the third year we are passing through. In certain areas this is the fourth year. Hon. State Minister in the Department of Agriculture, Shri Makwana, comes from Gujarat. He is aware of the situation. He should not feel embarrassed while putting up more demands on behalf of Gujarat. Sometimes it happens that we have always suffered when we have very important Minister in the Cabinet. He is not able to speak on behalf of Gujarat because he would be considered parochial. I would request Shri Makwana not to feel that parochial outlook; you do not possess that parochial outlook at all. So, you should act in the same way as you would act in an extreme difficult situation. I hope Shri Makwana has taken note of all the points that I have made. I would only reiterate that it is time to help us immediately.

SHRI VALAMPURI JOHN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, my State Tamil Nadu is experiencing a severe drought and the situation is so grave that I must say it is too grim for words. There is so much cry for water and water has become a scarce source. Almost all reservoirs have gone dry.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that Tanjore farmers have been deprived of their legitimate share of the Cauvery waters since 1974. In Tanjore delta alone the total loss of production of foodgrains is estimated at Rs. 150 crores and the loss of wages has been estimated as Rs. 50 crores. More than 10 lakh landless agricultural labourers have been hit badly. It is our charge against this Government that it had not realised the enormity of the problem and gravity of the situation and gravity of the situation in the proper perspective. The water shortage has become so acute this year that the people in the district of Tanjore have been forced to skip 'Kuruvai', samba cultivation is also threatened.

The 1924 agreement is very much valid even today. The Karnataka Government in gross violation of all rules has constructed additional dams to store water to irrigate 13 lakh acres without getting the permission from the Union Government, the Planning Commission and the Central River Water Commission. The result is that our reparian rights have been affected I would like to say that it is a very strange and piquant situation. In the North-eastern provinces, pockets have been marooned in water. There is inundation on a large scale and in most of the parts, the Prime Minister, the Government announces a lot of relief measures for flood-affected areas. Here in our part in Tamil Nadu and other Southern provinces we find another kind of strange situation year after year. We find that most of the people maroon in the streets of Madras where because of the beating sun there is not even a drop of water available. One part is marooned in water. In another part they have been simply going to the streets and finding a lot of women coming day in and day out for a bucket of water. In between we find a kind of government which I would not say is a prisoner of indecision but which is presiding over the derbis and not taking any kind of decision as a long-range programme to solve the problem of drought, water scarcity and famine permanently. There is need for appointing a tribunal for settlement of Cauvery water sharing issue without further delay and linkage of the major rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Cauvery in the South to solve the problems immediately engaging the attention of this Government.

Sir, in any other country, people would have taken up cudgels. The very system

[Shri Valampuri John]

would have collapsed by this time. In a way we treat people like wooden things. Nothing has happened. There is enough anger. And this anger should get only a focal point to smother every thing that we have achieved or claim to have achieved so far since Independence. There is enough anger among the people that their problem of scarcity of water, which is a basic, elementary problem has not been solved. But this anger is being suppressed because of religious beliefs and traditions. The same anger is being conditioned by cultural and sociological factors. This anger is not able to get a kind of passage because of various political reasons that are developing in this country. That is why I say in any other country people would have taken up cudgels. We are being treated as wooden things. There is no need for a Government if it says "there is no rain, so there is no water". Even now they have said that in 1990-91 in certain parts of Southern India, there would be no spell of rain and then there will be an acute shortage of water. Well ahead, there are scientists who can easily say, who can announce that ten years hence there will be no water, absolutely no water. Here I would like to say that we have ten or fifteen years to plan for but nothing is being done.

Karnataka Government, for example, I do not think, is a part of the nation, is a State in India. It behaves liek a principality. My grave concern is that we know from the history of the world that there are cases when waters have been shared by belligerent countries, fighting principalities. They have been fighting each other, shedding their blood, but even warring nations could share waters. But you call it a unified country, you call it a nation! But in a nation state we are not prepared to help another State. Karnataka is not prepared to help people of Tamilnadu, knowing fully well that we have been deprived of water sources for agriculture, for drinking purposes. This goes on. But the Central Government, despite its tall claims that it is unifying the whole edifice, it is catering to the economic needs of all people, has not been doing anything. It is simply sitting over this kind of a debris. What I say today may sound something very odd, but I warn this Government that they must pull up the Karnataka Government and tell them that the Tamils must have a feeling that they are a part of this nation and the basic problem of water should be immediately solved.

To tide over the situation, the Tamilnadu Government has been doing everything possible within its range of reach. One has only to pay a visit to Madras city to see how on a war footing my Government is meeting the demands of the people. We have been asking for Rs. 350 crores to tide over the situation. Again we have sent a proposal for an additional amount of Rs. 150 crores. But so far the Government has sanctioned only Rs. 34.3 crores. This is a meagre amount. Our situation is very grave. This amount will not meet even the elementary needs of the Madras city itself. So I would like to call upon the Minister and draw his attention to the grave situation that is coming up there. Even yesterday, in Madras, scientists have made an appeal to the Central Government that in the Neyveli Lignite Corporation area the colliery dens should not be closed. The colliery dens were found to contain a lot of water, and because four or five colliery dens have not been closed, at least an entire area—they say a district—has been saved from this kind of a scourge of water scarcity. So, I further appeal that the specific Ministry should take notice of this and in the Neyveli Lignite Corporation area the colliery dens should not be closed further. They should be kept open so that at least one district can tide over this kind of a grave situation.

Thank you.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस साल जो अकाल पड़ा है मेरे ख्याल से कई सालों पहले ऐसा अकाल पड़ा था हमारे यहां गुजरात में जो आज हालत है वहां 1812 में इससे पहले ऐसी हालत हुई थी उस समय अगस्त तक बारिश नहीं आई थी 175 साल

पहले ऐसा हुआ था। कल हमने कहीं पढ़ा कि सूर्य के आगे कोई चीज आ गई जिससे समुद्र का पानी गर्म नहीं हुआ और बादल नहीं बने वास्तविकता क्या है यह पता तो सरकार को लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम तो साइंटिस्ट जो कहते हैं उसको पढ़कर अपनी राय बनाते हैं। लेकिन इस साल जो हालत है वह बहुत बुरी है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल घास और पानी का है। पीने का पानी भी नहीं है। सरकार लोगों को कहां से पीने का पानी देगी, कहीं भी पानी नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा लांग टम प्रोजक्ट नहीं बनाया है जिससे समुद्र के पानी को मीठे पानी के रूप में परिवर्तित किया जा सके, जमीन में जो खारा पानी है उसको मीठा बनाया जाय। हमें इस तरह की टेक्नालाजी लेनी चाहिए। इसरायल बनाता है, हालैंड वाले बनाते हैं। हमें भी इस तरह का काम वहां से तकनीक लेकर शुरू करना चाहिए ताकि जब बरी हालत आय उस समय हम समद्र का जो पानी है, दूसरा जो पानी है उसको पीने लायक बना सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो अब सरकार को इसे करना चाहिए। यह शाट टर्म प्रोजक्ट है, लांग टर्म नहीं है। इससे हम ऐसी बुरी हालत से बच सकते हैं जो अभी चल रही है। हमारे यहां गुजरात में, जहां अकाल का तीसरा साल है, वहां आज भी कम से कम 8-10 लाख लोग रिलीफ वर्क में काम कर रहे हैं वहां पर जानवरों की हालत बहुत खराब है। गोट, जिसको बकरी कहते हैं गटा कहते हैं, वहां पर 20-25 रुपये में बिक रही है, 35-40 रुपये में लोग गाय बेच रहे हैं। उनके लिये चारा नहीं है वहां पर किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई है. उनके अन्दर फ्रस्टटयेशन आ गया है वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है। सरकार को किसी भी तरह से किसानों की हिम्मत बंधानी चाहिए। उन लोगों की हिम्मत न टूटे ऐसा सरकार को करना चाहिए ऐसा बहुत जरूरी है। कहीं से भी लाओ लेकिन उनको रिलीफ देनी आवश्यक है। केवल फाइलिंग से काम नहीं चलेगा। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि हमारे यहां अकाल का तीसरा साल है और जो वहां की एक्स-पेंडिचर लिमिट है उसको आधे से कम कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि 1985-86 में जो यह 144 करोड़ रुपये की लिमिट थी इस साल उसको 66 करोड़ रुपये क्यों कर दिया गया यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अकाल पहले से ज्यादा है पहले से बुरी हालत है ससे खर्चा ज्यादा होना चाहिए लेकिन इसे कम कर दिया गया है। यह कौन सी थ्योरी है, यह कौन सा एकाउंट लगाया कि 1985-86 में 144 करोड़ रुपये और इस साल उसको आधे से भी कम 66 करोड़ कर दिया है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मकवाणा साहब, आपने यह एकाउन्ट कैसे लगाया यह आप हमें समझायें आज की हालत में खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा ? यह तो लोगों को बवकूफ बनाने वाली बात है ज्यादा खर्चा होगा ज्यादा लोगों को रोजी देनी पड़ेगी ज्यादा कैटेल को घास देनी पड़ेगी। पानी कहीं न कहीं से आपको लाना पड़ेगा इससे खर्च दुगुना होगा, तिगुना होगा लेकिन इसके बदले आप आधे से कम पैसे देते हो, यह सब चीज नहीं चलेगी। आपके पास गेहूं पड़ा है कहीं कहीं पर तो सड़ रहा है लेकिन हमारे यहां खाने के लिए भी नहीं मिलता है। आप लोगों को खाने के लिए नहीं देते हैं। आप दूसरे राज्यों को देते हैं राजस्थान को देते हैं ग्रांट में दे सकते हो तो गुजरात राज्य को क्यों नहीं देते हो। क्या गुजरात इस देश का भाग नहीं है। हम लोग प्रदेशवाद को नहीं मानते हैं लेकिन अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो जिससे लोगों में प्रदेशवाद की भावना पैदा हो, हम गड़बड़ी वाला कोई काम करना पसंद नहीं करते, करना नहीं चाहते लेकिन हम को ऐसा बोलना पड़ता है। अभी तात्कालिक तौर पर आप एक लाख टन दे दीजिए गेहूं खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी को हम

[श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल]

धन्यवाद देते हैं उन्होंने दो लाख टन दिया था जो हम मजदूरों को गेहूं दे पाए। अब तात्कालिक तौर पर दो लाख टन दे दीजिए। आपको पानी भी देना पड़ेगा अगर इस महीने में हमारे राज्य में बारिश नहीं हुई तो पानी भी देना पड़ेगा, घास भी देनी पड़ेगी, अन्न भी देना पड़ेगा। हम आपको पेट्रोल देंगे सब कुछ देंगे लेकिन यह तब होगा जब सीजन लगे। मेहरबानी कर के सीलिंग हटा दो। आधे लोगों को जिन्दा रखना, आधे लोगों को मार देना, आधे केटल्स को बचा देंगे और आधे केटल्स को मारेंगे, आधे लोग रोजी पर जाते हैं उन में से आधे लोगों को रोजी मत दो या कम कर दो यह कैसा आपका अर्थमेटिक है, यह मेरी समझ में नहीं आता है पिछले साल 144 करोड़ दिया गया इस साल 66 करोड़ यह सीलिंग हटा दो। जितना चाहिए आपको उतना पूरा करना पड़ेगा। धन्यवाद।

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, I thank the hon. Chair for the opportunity given to me to take part in this discussion on the drought situation.

Sir, because of the eratic pattern of the rainfall in Tamil Nadu, we are facing acute drought this year, 1987. More than 75 per cent of the population have been affected in Tamil Nadu. Not an inch of Tamil Nadu received its normal rain in the year. But the Governmment of Tamil Nadu has risen to the heights to alleviate the sufferings on a war-footing basis. More than Rs. 200 crores were pooled in the right direction under the guidance of our Chief Minister, Dr. M.G.R.

Let me give some figures of the damage as well as the relief measures that have been taken so far. The deficiency of rain has been to the extent of more than 75 per cent in 15 districts, and in the rest the deficit of rain was above 50 per cent. Thirty lakh hectares of cropped area has dried up. More than 25 lakhs of cattle have been affected. In every district invariably thousands of coconut trees and other fruit-bearing trees have tried up and have been fully written off. Plantations like those of rubber, coffee; cardamom and tea also met the same fate. About 25 per cent of the yielding plantation crops have dried up in Tamil Nadu. In the Kanyakumari District, the loss of the perennial trees like those of coconut and rubber became very bad and unprecedented. Rough data reveal that the total loss of coconut and rubber trees in the Kanyakumari District would be more than Rs. 5 crores.

Normally, the District receives 1540 mm of rain annually. This year it got just 607 mm, the lowest for several decades.

I would also like to list out the drought-relief work undertaken by the State Government. First and foremost, in Tamil Nadu 175 lakh mandays have been utilised for drought relief work. More than 10,000 bore wells have been sunk, 5,000 open wells have been deepened, more than 2,500 new wells have been dug up.

In the metropolitan city of Madras, the only water supply source from the Red Hills Lake has dried up. The entire city water supply has been augmented from the source of giants wells which were dug up. The water is pumped by huge, giant pumps into the metro supply round the clock. Madras City and all other Municipal towns had been installed with steel tanks in every street. Water tanker lorries carry water and fill these tanks twice a day. More than 300 lorries have been pressed into service in Madras City alone. In the State as a whole about 4,000 lorries have had the conversion to carry water tanks for these purposes.

The complaint calls of the drinking water supply system are attended to round the clock and any complaint received is redressed within a few hours. All these have been done by the State Government. Special funds are now and then sanctioned by the State Government in advance anticipating the Centre's grants.

There is a proposal of Rs. 20 crore project to tap the ground water of Palar

River in Chingelput District for the supply of drinking water to the Madras City. I would request the Centre to come forward and give grant for this project.

We are facing drought for three consecutive years. In 1986 our Government had submitted a memorondum seeking assistance to the tune of Rs. 310 crores, but an amount of Rs. 31.77 crores was sanctioned on 21st October 1986 by the Centre.

On 12th March, 1987 our State Government submitted a memorandum to the Centre requesting a drought relief to the tune of Rs. 347.25 crores. A major portion of the sum requested has already been spent by the Tamil Nadu Government.

A meagre sum of Rs. 34.75 crores was sanctioned as an *ad hoc* grant by the Centre. The Centre has yet to take a deep study of the drought in Tamil Nadu and the huge expenditure incurred by the State Government.

I wish to remind the Centre regarding the Auditor-General's Report on the utilisation of drought relief funds sanctioned for the year 1971-72 when D.M.K. Government was in power. The report confirmed that only one tenth of the funds had been spent and there is no evidence or record for the balance of the spent amount. The Centre need not have any such apprehension. The party at the State Government has changed. I want to categorically bring in the difference in the existing situation. The Government itself is different Governmment and now it is headed by our Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Expenditure on drought relief has already been incurred by the State Government. Proper accounting by all the departments concerned in their concrete efforts has been properly maintained.

I conclude my request by asking the Centre to take immediate steps to sanction the drought relief fund of Rs. 347.25 crores immediately.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस माननीय सदन में सूखे के ऊपर चर्चा हो रही है और इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी ने भी इस देश में पड़ रहे सूखे के बारे में अपनी चिंता प्रकट की है । यह बात भी सही है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने भी सूखे के सर्वे के लिए अपनी टीमें भेजी हुई हैं और वे सर्वे कर रही हैं । बहुत अच्छी बात है । हमारे देश में सूखे की रोकथाम के लिए या कभी कभी जैसे बाढ़ आती है उसकी रोकथाम के लिए लम्बे टाइम की योजनाएं या प्रोजेक्ट क्या हों आज मैं इस बारे में अपने विचार नहीं रखना चाहता हूं । आज मुख्य सवाल यह है कि जो सूखा संकड़ों साल के बाद हमारे देश में आज आया है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों और फसलों की जो रक्षा करनी है उसके लिए क्या तरीका सरकार निकाल सकती है, हम सब मिलकर निकाल सकते हैं, इस पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । लम्बी योजना बनाइये ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी मगर जब किसान की फसल आज देहात में सूख रही है, बिजल उसको मिल नहीं है और नहर का पानी मिल नहीं रहा है तथा इस आसमान में आज 6 अगस्त के दिन भी बादल का कोई नामोनिशान नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि आज की चर्चा कीजिए कि इमीडियेट, तुरंत, फौरन हम क्या कदम उठायें ? यह मेरा निवेदन है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : त्यागी जी लंच के बाद कंटीन्यू कीजिए ।

The House stands adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty four minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.

श्री शांति त्यागी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैंने लंच से पूर्व इतना निवेदन किया था कि सौ साल में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा और यह बात मान ली गयी है ।

[श्री शांति त्यागी]

इस माननीय सदन में सूखे के निवारण के बारे में आज चर्चा हो रही है, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है । देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के ऊपर जो सूखे का संकट है, इस पर चिंता प्रगट की है और हमें आगाह किया है, सावधान किया है और देशवासियों से अपील की है कि सब मिलकर इसका मुकाबला करें, यह बड़ी अच्छी बात है ।

उपसभाध्यक्ष जी, सदन में बहस हो रही है सूखे के बारे में, यह बहुत अच्छी बात है । मैं यह कहना चाहता था कि सेन्टर की तरफ से सर्वे करने के लिए कि सूखे से कहां कितना नुकसान हुआ है, टीम गई हुई है राज्यों में । बहुत अच्छी बात है । बहस होती रहे, सर्वे की टीम अपना काम करती रहे मगर किसान को तो आज पानी की अड़चन है । मगर इन लम्बी अवधि की योजनाओं को पूरा करने में दस, पंद्रह , बीस साल तो लगेंगे और किसान का बेडा गर्क हो जाएगा फसलें सूख जायेंगी और देहात बर्बाद हो जाएंगे । यह देहात की बर्बादी नहीं है, यह तो पूरे देश का संकट है । इसलिए मैंने निवेदन किया कि आज वह काम कीजिए, वे कदम उठाइये जो आज के दिन जरूरी हैं । मसलन क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या आपने राज्य सरकारों से इस बात का निवेदन किया है या उन पर दबाव डाला है कि बिजली की सप्लाई जो वे अपने राज्यों में दस घंटे की दे रहे हैं, यह नाकाफी है । यह सूखी फसलों को नहीं बचा सकती है । आप कृपा करके जहां कहीं भी एअर कंडीशनर्स हों—साहबों के, मंत्रियों के बंगले में उन्हें बंद कराओं । शहर में फालतू जो बिजली खर्च होती है उसे बंद करो । टाटाओं की बिड़लाओं की बिजली काटो और सूखे हुए खेतों को बिजली दो । कम-से-कम 16 घंटे बिजली चलाओ । उपसभाध्यक्ष महोदय, नहरें भी काम कर रहीं हैं । यू० पी० में भी नहरें हैं । लेकिन उनमें पानी कम है । झीलें भी सूख गयी हैं । लेकिन जितना संभव हो नहरों में पानी दिया जाय और जब तक संभव हो उन्हें चलाया जाय तथा 16 घंटे बिजली दी जाय । कई दफे राज्य सरकार भी कमजोर दिखाती है, एक्सन नहीं लेती । मैंने पहले भी विकल जी के साथ मिलकर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप राहत कार्य और रिलीफ वर्क्स शुरू करें ताकि देहातों में गरीबों को, हरिजनों को, गिरिजनों को भूखे-नंगे लोगों को कुछ काम मिले । काम के बदले अनाज मिले । यह सब काम करने की आज जरूरत है । आप आगे की कार्यवाही करते रहिए कि अगले दस सालों में सूखे के निवारण के लिए क्या करेंगे । यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में सर्वे करने में, बहसें करने में कहीं किसान का बेड़ा गर्क न हो जाये, यह कृपा आप सुनिश्चित कर लें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यू० पी० की सरकार ने सौ करोड़ रुपया मांगा है । माननीय वीरभद्र सिंह जी ने और ढंग से बात कही । यू०पी० आबादी के हिसाब से देश का सब से बड़ा राज्य है । अभी विकल जी ने कहा चारे का इंतजाम नहीं है । हरा चारा सूख गया है और उम्मीद भी नहीं है कि कहीं पैदा हो जाएगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान का गन्ना सूख गया है, वह कहां से पैदा करेगा । टाटा–बिड़ला का कारखाना बिजली की वजह से आज बन्द हो जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा । कारखाना कल चल जाएगा । लेकिन जो गन्ना सूख जाएगा, चारे का खेत सूख जायगा, धान का खेत सूख जाएगा —वह दुबारा पैदा होने वाला नहीं है, अगले दफा पैदा होगा और हम देख रहे हैं कि यहां तोप और पनडुब्बियों के बारे में बहस है– मीडिया में भी और हाउस में भी । कहते है कि 80 करोड़ रुपए खाए गए । मगर पता नहीं किसने खाए है ।

कुल 1 अरब 10 करोड़ रुपया खाया। सूखे ने कई अरब रुपयों का नुकसान पहुंचा दिया मेरठ जिले को। तो इसकी चिन्ता करो, इसका उपाय बताओ। सरकार की कमी बताओ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यू० पी० सरकार ने जो मांग की है उसको आप स्वीकार कीजिए।

अंत में लम्बी चौड़ी बात न करते हुए मैंने जो पहले कहा, बिजली की बात कही, नहरों की बात कही उनको आप पूरा कीजिए। इसके अलावा मुनाफाखोर भी इस समय देश में सामने आएंगे, अनाज की तंगी करेंगे दालों व सब्जियों की तंगी करेंगे क्योंकि यह तंगी का वक्त है। दूध की कमी करेंगे तो ऐसे व्यापारियों पर आप कड़ी नजर रखें वरना ये देहात में उपद्रव मचाएंगे। देहात में रॉयट हो सकते हैं कम्यूनल की बात मैं नहीं कह रहा हूं वे भी हो रहे हैं लेकिन फूड के रॉयटस भी हो सकते हैं चारे के लिए रॉयट्स हो सकते हैं इस लिए आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपनी वितरण प्रणाली को मजबत करें ताकि देहात को फूड और चारा मिल सके।

इन शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार आज उस काम में लगे जहां बचाव करने की जरुरत है। परसों क्या होगा, उसको आप मत देखिए आपके अधिकारी लंबे चौड़े पोथे बनाएंगे, फिर उन पर बहस होगी वह काम आप करते रहिए लेकिन जो काम आज आप को करना है उसे पहले कीजिए ताकि किसानों के प्राणों को आप बचा सकें और उनको राहत दे सकें। धन्यवाद।

श्री नत्था सिंह (राजस्थान) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सूखे की चर्चा के लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सूखे की समस्या उत्तर भारत में एक दो प्रांतों को छोड़कर सब जगह पर भंयकर रूप धारण कर चुकी है। मैं जिस प्रांत से आता हूं, राजस्थान से वह हिन्दुस्तान में रिया के हिसाब से मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में लगभग हर साल ही सूखा पड़ता है। पिछले चार-पांच सालों से बहुत से जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब की बार राजस्थान में 27 जिले पूरे के पूरे अकाल की चपेट में आ गए हैं। इस कदर बुरी हालत में वे हैं कि हमें अनाज भारत सरकार खाने के लिए दे रही है लेकिन चारे के लिए वहां भीषण अकाल है और मवेशी मर रहे हैं। आप ताज्जब करेंगे कि जेसलमेर, बाढ़मेर, बीकानेर, पाली और जोधपुर ऐसे इलाके हैं जहां मवेशी आज बैठ जाता है तो वह उठ नहीं सकता है। पहले लोग कहते थे कि मवेशी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो खड़ा नहीं हो सकता लेकिन आज राजस्थान में पानी के अभाव में प्यास के मारे और पेट भर चारा न मिलने के कारण वह बैठ गया है और खड़ा नहीं हो सकता है। उसके पेट के नीचे दो डंडे डालकर चार-चार पांच-पांच आदमी दोनों तरफ से उठाते हैं और थोड़ा बहुत उसको कहीं से लाकर खिलाते हैं तब वह उठ पाता है। आज राजस्थान में तूरा, करनी और किसी प्रकार का चारा नहीं मिलता है। आज ऐसी हालत राजस्थान की है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि मंत्री जी आपने अति कृपा की है राजस्थान पर आपने काफी दिया है राजस्थान को लेकिन हिन्दुस्तान के तमाम प्रांतों में राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां सूखे का असर इतनी मात्रा में हुआ है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तुरन्त राजस्थान को चारे, अनाज और पैसे के रूप में ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कोशिश करें।

माननीय मंत्री जी इस सूखे की चपेट में मेरे पूर्वी राजस्थान में जिस जिले से मैं आता हूं भरतपुर हां लगातार दो-तीन साल से बारिश नहीं हो रही है इसी जिले का नहीं पूरे राजस्थान का बुरा हाल है। कुंएं का पीने का जो

[श्री नत्था सिंह]

पानी है वह काफी नीचे चला गया है या ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं पानी के लिए उनका स्तर 25-25 फीट 30-30, 40-40 फीट नीचे उतर गया है । पानी उनमें रहता नहीं है हमारे भरतपुर अलवर पूर्वी राजस्थान में कूंए पर हमारी माताएं-बहनें सुबह उठकर पानी लेने जाती हैं जो सुबह जाती हैं वे तो पानी ले आती हैं लेकिन जो पीछे रह जाती हैं और 6 बजे के आस-पास पानी लेने जाती हैं उनको कीचड़ वाला पानी मिलता है और बहुत सी बहनें तो बिना पानी के ही लौट आती हैं । यह हालत है राजस्थान में पीने के पानी की । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह राजस्थान में चाहे टैंक के द्वारा या किसी और के द्वारा पानी की व्यवस्था करायें । मुझे दुख होता है कि राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में तो और भी बुरी हालत है उस हालत को देख कर हमें अफसोस होता है और हम यह कहते हैं कि हम 40 साल की आजादी के बाद भी इतना नहीं कर सके कि वहां के भाइयों को, बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, साथियों को पानी पीने का मिले। पशुओं के लिए पानी मिले । आज भी उनको 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है । यह पानी उनको ऊंट गाड़ी से ट्रकों से और किसी दूसरे तरीके से, लाना पड़ता है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राजस्थान के लिए आपने जो पहले दिया है वह बिल्कुल नाकाफी है । राजस्थान में भंयकर अकाल है । आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जितनी सहायता कर सकें उतनी पीने के पानी की, अनाज के चारे की व्यवस्था करने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, सूखे पर चर्चा के लिए मुझे जो अवसर दिया गया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस वर्ष पूरे देश में और देश के कई प्रांतों में सूखा पड़ा हुआ है । हमारे देश के 406 जिलों में से 206 जिले सूखे से प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश में 45 जिले है उन जिलों में से 43 जिले पूरी तरह से सूखे के चपेट में है । मैं इन्दौर क्षेत्र जो मालवा क्षेत्र में है, से आता हूं जहां पर कभी सूखा नहीं पड़ा, जहां कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक विपदा नहीं हुई । जहां कभी मनुष्यों को किसी प्रकार क कोई तकलीफ नहीं हुई । उस इलाके में आज भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । वैसे मध्य प्रदेश लगातार 3 वर्ष से प्रभावित होता आ रहा है । कभी अधिक बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है । इसप्रकार से मध्य प्रदेश तीन साल से लगातर प्राकृतिक विपदाओं से घिरा हुआ है । इस वर्ष मध्य प्रदेश काफी सूखे की चपेट में है । मेरे पास मध्य प्रदेश के सभी जिलों के आंकड़े हैं । हमारे मध्य प्रदेश में खाली एक ऐसा जिला है जहां सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा हुई और उसके बाद 25 परसेंट से कम वर्षा वाले जिले हमारे मध्य प्रदेश में 9 हैं और इसके बाद 26 परसेंट से 50 परसेंट तक कम वर्षा वाले 20 जिले हैं और सामान्य से 50 परसेंट से अधिक कम वर्षा वाले 15 जिले हैं । इस प्रकार से मध्य प्रदेश के करीब-करीब सभी जिलों में सूखा पड़ा हुआ है ।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अन्य प्रांतों को सहायता दें उससे अधिक हमारे प्रदेश को दें क्योंकि मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ, हरिजन और आदिवासी बाहुल्य वाला प्रान्त है ।

मान्यवर, इस वर्ष मध्य प्रदेश में मानसून जून के दूसरे सप्ताह में शुरू हो गया था । इस प्रकार से मानसून आने के पहले जुलाई के प्रथम सप्ताह में थोड़ा बहुत पानी गिरा । उसके बाद आज तक एक महीना हो गया है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी बरसात नहीं हुई है । मध्य प्रदेश के

करीब-करीब सभी जिलों में खरीफ की फसल बो दी गई है। गरीब किसानों ने खाद, बीज और अन्य सामग्री अपने खेतों में डाली। लेकिन दुर्भाग्य से प्राकृतिक विपदा के कारण पूरी तरह से उनकी फसल चौपट हो चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश के तीन जिले ऐसे है, रीवां, सतना और सीधी, जहां पर बहुत ही कम मानसून आया। वहां पर आज तक भी लोग अपनी बोनी नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे गरीब किसानों के लिए जो खरीफ की फसल बो चुके हैं, जिनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है, उन किसानों की मदद करने की आवश्यकता है। चाहे आप उनका खाद, बीज और कर्जा माफ करें या देंउनको किसी प्रकार की अन्य कोई राहत दें।

सूखे की स्थिति के साथ-साथ हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों ने पेयजल के ऊपर अपने विचार रखें। मध्य प्रदेश के 381 नगरों और 15,577 गांवों में पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। जहां पहले के क्षेत्र में 20 और 15 फुट पर पानी मिल जाता था, आज उस इलाके में तीन सौ, चार सौ और पांच सौ फुट तक पानी नीचे चला गया है। सभी कुएं सूख चुके है और तालाबों में पानी नहीं है। नदियों में पानी सूख चुका है। यहां तक कि जिन गहरे नलकूपों में पानी मिलता था, वे भी सूख चुके है। किसानों के पास सिंचाई के अन्य कोई साधन नहीं हैं। उनका कार्य सिंचाई बन्द पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि आज इस देश में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, इन सब स्थानों में जल-स्तर क्यों नीचे जा रहा है क्या इसके ऊपर हमने कोई अध्ययन किया है? इस संबंध में हम क्या करने जा रहे हैं? इस विषय पर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और इस काम के लिए अच्छे वैज्ञानिकों को लेना पड़ेगा और इसका परीक्षण कराना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर यह जल स्तर नीचे जाता रहा तो आगे क्या स्थिति होगी इस पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। आगे हम लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाऐंगे यह स्थिति पैदा होने वाली है। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने सभी कामों को छोड़कर वृक्षारोपण के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जो लोग जंगलों को काटते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको जिस प्रकार मर्डर के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता है उसी प्रकार से उनको भी कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए। जो लोग जंगलों को काटते हैं या प्राकृतिक सम्पत्ति को नष्ट करते हैं उनके लिए हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा और तभी इस देश की हरियाली और प्राकृतिक सम्पदा को बचाया जा सकता है। जब तक हम इस प्रकार की कोई कठोर व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम देश के प्राकृतिक सौंदर्य और जंगलों को काटने से रोक नहीं पाऐंगे। इसके लिए आपको कठोर कानून बनाना पड़ेगा और वृक्षारोपण के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय, पेयजल के साथ पशु चारे की समस्या भी निर्मित हो चुकी है। आज मध्य प्रदेश के सभी जिले सूखे की चपेट में हैं। किसान अपने मवेशियों के लिए जुलाई माह तक घास और भूसा सम्भाल कर रखे गये। अगस्त माह में बरसात में पशुओं के लिये घास हो जायेगा। किन्तु सूखे की स्थिति से मवेशियों को खिलाने के लिए कोई घास या चारा नहीं है। मवेशी पालने वालों के पास मवेशियों को खिलाने के लिये चारा नहीं है। यहां तक स्थिति निर्मित हो गई है कि जिन किसानों के पास मवेशियां हैं वे झाड़ों का पत्ता मवेशियों को खिला रहे हैं। वहां पर जो झाड़ हैं वह इस तरह से नष्ट हो रहीं हैं। यदि हमने इस संबंध में तुरन्त कदम नहीं उठाये तो हमारे देश के कई भागों में मवेशी मरने की स्थिति में आ जायेंगे और एक बहुत बड़ा खतरा मवेशियों का हमारे सामने पैदा हो जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे देश में जहां पर भी घास-फूस उपलब्ध हो सकता है उन लोकों में

[श्री राधाकिशन मालवीय]

चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जहां पर मवेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर मवेशियों के लिये घास और चारे को भेजने का प्रयत्न किया जाये। शासन से मेरा यह भी अनुरोध है कि वहां पर कैटल कैम्प की व्यवस्था की जाय ताकि वहां पर उनको रियायती दर पर घास और चारा उपलब्ध हो सके।

मान्यवर, पशु चारे के सवाल के साथ साथ हमारे प्रान्त में उन गरीब लोगों की, जो खेतिहर मजदूर है जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं उनको भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आज गांवों में रहने वाले मजदूर पूरी तरह से बेकार बैठे हुए हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार राहत कार्य चालू कर रही है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा प्रान्त है और पिछड़ा प्रान्त होने के बावजूद वह पिछले तीन सालों से लगातार प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता आ रहा है और इस वर्ष तो वह एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश 1984-85 से 1986-87 तक एक न एक प्राकृतिक विपदाओं से घिरा हुआ है। अभी वर्तमान तीन माह जो गुजर चुके हैं, अप्रैल से जून तक मध्य प्रदेश सरकार ने इन तीन महीनों में 43 करोड़ 66 लाख रुपये इस राहत कार्य के ऊपर खर्च किये हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता की भी मांग की थी और मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन अनाज मध्य प्रदेश सरकार को दिया जिसका मूल्य 15.50 करोड़ रुपया होता है। मान्यवर वहां पर इस प्रकार की भंयकर स्थिति मजदूरों की निर्मित हो गई है कि अगर उन मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई तो वहां एक ओर पीने के पानी की तकलीफ है वहां दूसरी ओर हमारे इन गरीब भाइयों के सामने एक और मुसीबत, खाने की उनके सामने आ जायेगी। मान्यवर, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 लाख लोग रोज रोजगार में लगे हुए हैं। यदि हम अनुमान लगायें कि अगर एक व्यक्ति को दस रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है तो 10 करोड़ रुपये शासन को वहां पर प्रति माह खर्च करने होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है और वह इतना खर्च नहीं कर सकती है। मेरा माननीय मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध है कि जो हमारे गांवों में रहने वाले गरीब मजदूर किसान हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको आज राहत की बहुत जरूरत है उनके लिये राहत कार्य वहां पर प्रारम्भ किये जायें और सबिसडी के आधार पर उनको खाना, अनाज और रोजगार की व्यवस्था की जाये मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्री केशव प्रसाद शुक्ल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर सूखे पर चर्चा हो रही है और मेरे पूर्व वक्ता मालवीय जी ने हमारे मध्य प्रदेश के बारे में अभी कहा है, वहां की स्थिति का चित्रण किया है वहां की स्थिति का विशद वर्णन उन्होंने किया है। यह सूखा जो है यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा है। 1939 में बंगाल में सूखा पड़ा था जब अंग्रेजों का राज था। उस समय 40 लाख लोग मरे थे यह सूखा एक प्रान्त का था लेकिन अब तो पूरे उत्तर भारत में सूखा पड़ा हुआ है। चार-छ राज्यों को छोड़ कर बाकी सभी जगहों पर सूखे की भयावह स्थिति है और इसका सामना करने के लिये राज्यों की सरकारों की वित्तीय स्थिति उसके अनुरूप नहीं है। केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता की आवश्यकता है। अकाल आ गया है और उसका युद्ध स्तर पर सामना करना पड़ेगा तभी हम लोग उसका मुकाबला कर सकेंगे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह नेशनल केलेमिटी है जो हमारे सामने आई है और विरोधी दल इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोच रहे हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस समय हम सब को मिल कर इस स्थिति का सामना करना होगा। हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसके लिये एक कमेटी बनाई

है और वह कमेटी इस पर विचार कर रही है तथा अपनी टीम भी राज्यों में भेज दी है सब जगह सर्वेक्षण कर रही है इस पर समय रहते उन्होंने कदम उठाया है इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सब से बड़ी भयावह स्थिति जो है वह आज गल्ले की नहीं है अभी दो तीन महीने के लिये गल्ला किसानों के पास पड़ा है लेकिन सब से विकट स्थिति पीने के पानी की है। कूएं, तलाब नदी-नाले सब सूख गये हैं हमारे यहां मध्य प्रदेश में सभी जगह सूखा पड़ा हुआ है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां लगातार तीन साल से कुछ इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। पिछले साल इन्दौर संभाग में सूखा पड़ा था और इन्दौर संभाग का जलस्तर 600 फुट नीचे चला गया है जैसे कि अभी मालवीय जी ने आंकड़े दिये हमारे यहां 16 जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा नहीं हुई। उन जिलों में जलस्तर और भी नीचे चला गया है और बहुत जल्दी वहां पर लोग पानी के बिना मरने लगेंगे। इसलिये गल्ले का प्रबन्ध बाद में होगा पहले पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिये मंत्री जी से मैं कहूंगा, नहीं तो मनुष्य और पशु दोनों मरने लगेंगे। इसलिये गहराई तक खोदने वाली 12 ड्रिलिंग मशीनों की मध्य प्रदेश शासन ने मांग प्रस्तुत की है, जिससे मध्य प्रदेश में गहराई तक कूएं खोद कर पानी निकाला जा सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तुरंत यह ड्रिलिंग मशीनें मध्य प्रदेश शासन को भेजने की व्यवस्था करें। जहां-जहां भी पानी का स्तर नीचे चला गया है वहां इस तरह की मशीनें भेजी जाएं। हमारे यहां पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां पर गहराई तक खोदने वाली मशीनों की बहुत जरूरत है। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन है उसमें नजदीक पानी मिल सकता है लेकिन हमारे यहां पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए वहां पर पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए सब से पहला निवेदन मेरा यह है कि जल की व्यवस्था की जाए। जल की व्यवस्था करने के लिए चाहे जैसे भी हो, वैसी व्यवस्था करनी चाहिये। दूसरी चीज है पशुओं के चारे के लिए। पानी न मिलने की वजह से पशुओं के लिये चारे की पैदावार नहीं हुई है। पशु आज मर रहे हैं। राजस्थान के बारे में एक माननीय सदस्य ने अभी बताया है। मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है मध्य प्रदेश में जंगल बहुत है। जंगलों में घास होती है। जंगलों का जो फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट बना हुआ है। इसके कारण वहां मवेशियों को चराने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। इस कानून में आपको शिथिलता लानी पड़ेगी। जंगल में जो सूखी घास है उसको कटवा कर मवेशियों को देने के लिये बांटी जाए और जंगलों में जगह-जगह पर मवेशियों के रहने के लिए स्थलों का निर्माण किया जाए जिससे मवेशियों के चारे का प्रबन्ध हो सके। राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं जिससे खेतीहार मजदूर, गरीब किसान, हरिजन, आदिवासी लोग भूखे न मरने पाएं। उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार में मजदूरी के रूप में उनको गल्ला भी दिया जाए। उस गल्ले के वितरण की व्यवस्था आपको ठीक से करनी पड़ेगी क्योंकि वितरण में भी संकट के समय में भी कुछ लोग पैसा बनाना चाहते हैं ब्लैक मार्किटिंग करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट रूप से आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमारी जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उन दुकानों का गल्ला कहीं व्यापारियों के हाथ में न पड़ जाए इसके लिए भी आपको कदम उठाना पड़ेगा और नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। तीसरी चीज यह है कि हमारे यहां पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि पहले तालाब कूएं बावड़ियां जो बनाये जाते थे वह केवल इसलिए कि पानी का स्तर नीचे न जाने पाये। आजकल तो रोजगार पैदा करने के लिए जो तालाब बनते हैं उनको बांध दिये हैं लेकिन हमारे यहां तालाबों का कमी हो गया है। मेरा सुझाव है कि जितने तालाब आदि हैं उनका सबका सरवाई कर दिया

[श्री केश्व प्रसाद शुक्ल]

जाये, वे किसी व्यक्ति के न रह जायें। क्योंकि तालाब जो खुदवाये जाते थे वे खेती के लिए नहीं खुदवाये जाते थे उनको पब्लिक को डेडीकेट कर दिया जाता था और सारी पब्लिक के विस्तार के लिए पानी हो जाता था लेकिन आज वे इवेंट प्रापर्टी हो गये हैं। मेरा सुझाव है कि कानून में ऐसा संशोधन कर दिया जाये, जो माल कानून है उसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाये कि माल कानून में सुधार करके जितने टैंक हैं उनको सरकारी घोषित करें और उनमें राहत कार्य के द्वारा मिट्टी आदि डलवाकर उनको पूर्व स्थिति में लायें ताकि हमारे यहां का जलस्तर जो नीचे हो गया है वह कुछ हद तक ठीक हो जाये। यह तो लांग टर्म है। लेकिन अभी तो जो सरकारी तालाब हैं उनको जरूर बनवा दिया जाये राहत कार्य शुरू करके इससे हमारे जल का स्तर नीचे नहीं गिरेगा, आगे चल करके जल स्तर ठीक रहेगा।

इसी तरह से हमारी वितरण की प्रणाली के ऊपर ध्यान देना जरुरी है और पशुओं के आहार के बारे में बहुत ही सतर्कता से विचार करना है। इन सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय में मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है सूखे के कारण देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गांवों में रहने वाले किसान मजदूर, उनके पशु सब परेशानी की हालत में हो गये हैं। जो राष्ट्र में एक ऐसा संकट पड़ा है इससे सारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों की हरी फसल, लहलहाती फसल नष्ट हो रही है पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लाखों पशु मर रहे हैं पूरे देश में एक अकाल का राष्ट्रीय संकट व्याप्त हो गया है। ऐसे दौर में हमारी सरकार और देश के सारे विरोधी दल के नेताओं का यह कर्तव्य है कि इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में राहत कार्य एक मन से इकट्ठे होकर करें। ऐसी भीषण अकाल की स्थिति में इस देश के विरोधी दल के लोग कितने जनद्रोही, राष्ट्रद्रोही और गद्दार हैं कि जब देश के करोड़ों करोड़ इन्सानों का जीवन खतरे में है तो ऐसे वक्त में भी कुर्सी की लड़ाई को वे प्राथमिकता दे रहे हैं। कुर्सी से बड़ी चीज है जनता की सेवा, राष्ट्र की सेवा जनता का कल्याण। ये इनके लिए कोई चीज नहीं है। भारत की करोड़ों जनता भी इस बात को देख रही है कि जनता का नाम लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये जनद्रोही और राष्ट्रद्रोही कितने हमारे भारत के वफादार हैं कितना जनता के ऊपर सोचते हैं और जनता के लिए इनके मन में सम्मान है। रेडियो आकाशवाणी टेलिविजन अखबारों के माध्यम से जनता यह सुन रही है कि विरोधी दल के लोग सदन का बहिष्कार किये हुए हैं। दिल्ली में सदन में बहिष्कार करके घर बैठे हैं ये भी सोच रहे होंगे कि देश का करोड़ों करोड़ रुपया जो सर्वेंट आफ द पीपुल जनता के सेवकों पर खर्च होता है वे हमारी जनता के प्रतिनिधि कैसे हैं। कितना उनके मन में जनता के प्रति आदर है, कितना भाव है, इस प्रश्न पर वे विचार कर रहे होंगे। जब कोई विदेशी हमला करता है तो उस वक्त सारा राष्ट्र एक होकर खड़ा हो जाता है तो विदेशी हमले के प्रति देश में जैसी एकता की भावना पैदा होती है।

आज हिन्दुस्तान के विरोधी दल के नेताओं का और सारे देश की पार्टियों का प्रधान मंत्री से लेकर विपक्षी दल के सभी लोगों का यह राष्ट्रीय धर्म है, यह महान राष्ट्रीय वक्तव्य है यह जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं इस महान संकट की घड़ी में जब सारा उत्तर भारत अकाल की छाया में अपना जीवन बिता रहा है, जब करोड़ों किसानों की फसल, लहलहाती फसल नष्ट हो गई है

सुखाड़ के कारण, जब उनके लाखों पशु मर रहे हैं, जब सब गांवों के कुंओं का पानी सूख गया है ऐसी हालत में देश के सभी दलों के नेताओं का यह धर्म है कि इस राष्ट्रीय संकट की बेला में एक मन से वह तब तक अकाल के राहत के कार्य को करते रहें जब तक कि अकाल खत्म नहीं हो जाता।

महोदय, इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, इनकी कोई दृष्टि नहीं है इनके मन में कोई देश, कोई जनता कोई ला हो, यह बिल्कुल नहीं है। यह केवल चरित्र-हत्या, जनघात राष्ट्रघात और कुर्सी की लड़ाई ही इनकी प्राथमिकता है।

आदरणीय महोदय, मैं सरकार का ध्यान और प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने सूखे से निपटने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है राज्य सरकारों को प्रधान मंत्री की तरफ से निर्देश दिये गए हैं कि राहत के कार्य फूड फार वर्क स्कीम के अन्तर्गत सारे देश में राहत का कार्य जोरदार ढंग से किया जाए। इसमें सरकारी ताकत भी लगे और जो गैर-सरकारी ताकत है उसको भी इस्तेमाल किया जा

मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज ही हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों और यहां तक कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनकी मीटिंग आज ही बुलाएं और राष्ट्र के इस प्रश्न पर पूरी नेशनल केलेमिटी, राष्ट्रीय संकट को किस हद तक हम दूर किर सकते हैं, कितनी हम करोड़ों इंसानों के जीवन में मदद कर सकते हैं, इस सवाल पर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, सभी विरोधी पार्टी के नेताओं और सभी गैर-सरकारी संस्थाओं को भी इस काम में बुलाएं और बुलाकर कर एक सर्व-सम्मत राष्ट्रीय मतैक्य की स्थापना करके राहत के कार्य को युद्ध स्तर पर करवाया जाए क्योंकि गांवों की हालत जो है इस समय उत्तर भारत के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के इलाके में, तमिलनाड, में, इस सूखे से निपटने के लिए लाखों-करोड़ों लोगों की आवश्यकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have not included Maharashtra.

श्री कल्पनाथ राय : महाराष्ट्र को भी मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो हिन्दुस्तान का 75 प्रतिशत इलाका गांव सूखे पड़े हुए हैं, उस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय मकैक्य की स्थापना करके, जिसमें लाखों लोग लगेंगे, तो थोड़ी बहुत हम राहत दे सकते हैं। इस कार्य के लिए सरकार को सारे विरोधी दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए, गैर-सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी का काम करती हैं, उनको भी बुलाना चाहिए, वालंटरी आर्गेनाइजेशंस जो विभिन्न प्रांतों में हैं उनकी भी सेवायें ली जानी चाहिए और जनता की मदद के लिए इन सारी ताकतों को इक्टा होकर इस समय काम करना चाहिए। इस सूखे से निपटने के लिए एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है। इस कार्य को तुरंत करना चाहिए। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी और हमारे मित्र श्री रामानन्द यादव दोनों के माध्यम, से सरकार से अपील करता हूं कि वह तुरंत आज ही इस अकाल, ड्राउट, सूखे के संबंध में विचार-विमर्श के लिए सबको बुलायें चाहे कोई आए न आए, लेकिन जनता को यह जानना चाहिए कि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री ने इस सूखे की समस्या से निपटने के लिए सभी लोगों को बुलाया है। सब को ताकत से इस राष्ट्रीय संकट को दूर करने का प्रयास किया है। यह बात आज ही की जानी चाहिए क्योंकि इसमें जितने मिनट या घंटे देरी होगी उतने ही हमारे जनता का अहित होगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी सभी प्रांतों के मुख्य मंत्रियों को एक गोलमेज कान्फेंस बुलाएं और उनके बीच में भी प्रांतीय स्तर पर इस सूखे के संकट को हल करने के लिए सारी राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर कार्यक्रम अपना कर के इस राष्ट्रीय संकट को दूर करने का प्रयास करें। आदरणीय उप-

[श्री कल्पनाथ राय]

सभाध्यक्ष महोदय, 40 वर्ष की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान में बाढ़ एवं सुखाड़ का संकट रहा है । कभी बाढ़ का संकट कभी सुखाड़ का संकट, कभी दक्षिण भारत में सूखा, कभी उत्तरी भारत में सूखा, कभी गुजरात में सूखा, कभी आसाम में सूखा यानी इन समस्याओं से हमारा देश पिछले 40 वर्षों से लगातार जूझता रहा है । मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ और सूखड़ की समस्या से निपटने के लिए निश्चित सरकार एक लांग टर्म पालिसी और एक पालिसी अख्तियार करे कि हम इतने दिनों के अन्दर हिन्दुस्तान की जो सिचाई योग्य जमीन है उस पर सिंचाई का इंतजाम कर देंगे और जो हमारे देश का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है इसको वेस्ट नहीं होने देंगे । वाटर कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में जितना पानी प्रकृति से पैदा होता है अंडरग्राउंड या ऊपर से जो पानी बरसता है उसका 85 फीसदी पानी वेस्ट हो जाता है और उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं । अगर हमारे देश में आज प्रकृति ने जो साधन दिया है, जो पानी का हमारे देश को साधन दिया है यदि उस साधन का इस्तेमाल किया जाए, वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक ढंग से अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो हम बाढ़ और सूखाड़ के संकट से निपट सकते हैं । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार इस सदन में पिछले 13 वर्ष से सरकार से निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो बाढ़ और सुखाड़ के शिकार होते हैं लेकिन जहां इतना पानी ईश्वर ने दिया है कि यदि उस पानी को चैनलाइज किया जाए तो हम बाढ़ और सुखाड़ के संकट को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । मैंने सरकार से कहा कि बिहार में शारदा नदी, घाघरा नदी और राप्ती नदी इन तीनों नदियों का जो उदगम है वह नेपाल है । ये नदियां हर बरसात में ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि पूर्वी-उत्तर प्रदेश और बिहार में करोड़ों अरबों की संपत्ति केवल बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और यहां बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद रबी की फसल की बुवाई आती है तब सुखाड़ के संकट के कार इस लाके की फसल नष्ट हो जाती है । हमने सरकार से बार-बार निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में टिहरी डैम जहां से गंगा नदी निकलती है वहां भारत की सरकार और रूस की सरकार ने टिहरी डैम बनाने का भी फैसला किया है उसके बनने से जहां हम उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की बाढ़ की समस्या को हल कर लेंगे वही दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में करीब 20 हजार मेगावाट बिजली को पैदा करेंगे इसलिए इस काम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं नेपाल सरकार से वार्ता करके टिहरी डैम के साथ करनाली डैम, भालू बांध, पंचेश्वरी डैम का निर्माण करना चाहिए जहां नेपाल खत्म होता है और हिन्दुस्तान शुरू होता है, वहां राप्ती नदी पर भालू बांध का निर्माण किया जाय । जहां घाघरा नदी हिन्दुस्तान में प्रवेश करती है, नेपाल में घाघरा को करनाली कहते हैं और हिन्दुस्तान में सरजू या घाघरा कहते हैं जहां यह करनाली नदी खत्म होती हैं और हिन्दुस्तान में सरजू या घाघरा के नाम से जानी जाती है, वहां करनाली डैम का निर्माण किया जाय और पन्चेश्वरी डेम शारदा नदी पर, जो नेपाल से निकल कर हिन्दुस्तान में प्रवेश करती है, उस स्थान पर इसका निर्माण किया जाय । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करके इन तीनों डैमों का निर्माण कराए विश्व बैंक की सहायता लेकर के, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिन्दुस्तान के बड़े भूभाग को बाढ़ की विभीषिका से हम बचा सकते हैं और इन तीनों डैमों से 25 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा । इस 25 हजार मेगावाट बिजली से उत्तर प्रदेश बिहार, बंगाल के हर गांव में ट्यूबवेल के माध्यम से हम अण्डरग्राउण्ड वाटर को बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन तीनों डैमों के निर्माण से 25 हजार मेगावाट बिजली बनेगी, 5 हजार मेगावाट बिजली बनेगी टेहरी डैम के निर्माण से और ब्रह्मपुत्र, जो कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी नदी, है, जिसमें अथाह जल है, सका उदगम से निकल कर

सारा पानी बंगाल की खाड़ी में वेस्ट चला जाता है, वहां पर भी हम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक जनरेशन करें तो ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदियों से, एटोमिक एनर्जी के भूतपूर्व चेयरमैन सेठना के अनुसार 15 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है । इस प्रकार एक तरफ 25 हजार मेगावाट बिजली, दूसरी तरफ 5 हजार मेगावाट बिजली और यह ब्रह्मपुत्र से 15 हजार मेगावाट बिजली इस प्रकार 45 हजार मेगावाट हाइड्रो- लेक्ट्रिक जनरेशन का निर्माण इन नदियों पर डैम बनाने से होता है .

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सारा पानी बहकर समुद्र में चला गया इस पानी को रोकना और अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर उसे बदलकर नहरों के माध्यम से जनता को समर्पित करना जब तक इस सवाल पर सरकार ध्यान नहीं देगी प्राथमिकता नहीं देगी तो काम नहीं बनेगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं--उत्पादन, उत्पादकता और बेरोजगारी के संकट का निवारण ये तीन हमारे उद्देश्य हैं लेकिन हम देखते हैं आज गांवों के लड़के किसानों के लड़के चूंकि खेती एक घाटे का सौदा बन गया है ,खेती मुनाफे का सौदा नहीं है, इसलिए किसानों के लड़के 200/- 300/- या 400/- रुपए की नौकरी के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं वह खेती नहीं करते ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले की खेती मे और आज की खेती में एक बुनियादी फर्क है । आज की खेती एक उद्योग बन गयी है आज किसान के खेत में ट्रेक्टर चलता है ट्रेक्टर से जुताई होती है, किसान के खेत में पेस्टीसाइड -इनसेक्कटीसाइड का इस्तेमाल होता है जो कारखानों में बनता है। किसान के खेत में बिजली से, ट्यूबवेल से पानी जाता है । किसान के खेत में फर्टिलाइजर लगता है और इन सारी चीजों पर खर्च करने के लिए उसे कोपरेटिव बैंक से या दूसरे बैंकों से कर्ज लेना पड़ता हैं। आज अगर हिन्दुस्तान में सर्वे कराया जाय तो आप पाएंगे कि आज हिन्दुस्तान में 90 परसेंट किसान हर गांव में कर्जे से लदे हुए हैं । आज खेती बिना पैसे के नहीं हो सकती और अगर किसान कर्ज लेकर खेती करेगा खेत में अगर वह 3000/- रुपया लेकर खच करेगा फर्टिलाइजर या ट्यूबवेल पर या ट्रक्टर पर या पेस्टीसाइड या इनसेक्टीसाइड पर और अगर बाढ़ आ गयी उसकी पूरी फसल नष्ट हो गयी तो उसको यह 3000/- रुपए के 6000/- रुपए देने पड़ेंगे । अगर उसने खेती की, और सूखा पड़ गया तो फसल नष्ट हो गयी । परिणामस्वरुप वे किसान कोआपरेटि बैंक या बैंक से कर्जा लेते हैं और अपनी खेती में लगाते हैं सूखे के कारण 90 प्रतिशत किसान कर्जदार हो गए हैं । जो देश की दौलत को पैदा करते हैं वे किसान आज कर्जदार बन गए हैं । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज खेती का सौदा घाट का सौदा बन गया है । किसान का लड़का 200, 300 या 400 रुपए की नौकरी के लिए दरदर की ठोकरें खा रहा है, । वह अपनी खेती का काम नहीं करना चाहता क्योंकि खेती घाटे का सौदा बन गया है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान जहां कि खेती इकोनोमी का मुख्य आधार है। हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था और गांव की अर्थ व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब बाढ़ और सुखाड़ के संकट से हिंदुस्तान के गांव को बचाया जा सकेगा । आज के वैज्ञानिक युग में सबसे बड़ा सवाल है पानी का उपयोग । पिछले 40 वर्षों के अन्दर हम ने अपने पानी के इस्तेमाल के सम्बन्ध में कोई ठोस और समयबद्ध योजना बनायी है ? जिस मुल्क के अंदर 85 प्रतिशत पानी बहकर नदियों में चला जाता है और उसका उपयोग नहीं हो पाता यह हमारे देश की गरीबी का प्रमुख कारण है । आज हिंदुस्तान सबसे गरीब क्यों है ? यह बनियादी प्रश्न है कि हम पानी का इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस प्रश्न पर हिंदुस्तान की कैबिनेट को विचार करना चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को विचार करना चाहिए ।

[श्री कल्पनाथ राय]

हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों को शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूरों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन, उत्पादकता और बेरोजगारी के सवाल को हल करने के लिए हमें इस प्रश्न को राष्ट्रीय संकट मानकर एक लांग टर्म पालिसी बनानी चाहिए हिंदुस्तान की खेती के लि एक लांग टर्म पालिसी भारत की सरकार बनाए । आज इससे बड़ा संकट भविष्य में बनने वाला है । आनेवाला संकट इससे बड़ा होगा क्योंकि हिंदुस्तान की खेती बिना पैसे के नहीं हो सकती । आज आप सर्वे कीजिए तो पाएंगे कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं । स्कूटर बनाने वाला का व्यक्ति किसी गांव के संपन्न किसान से भी ज्यादा सुखी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

श्री कल्पनाथ राय : इसलिए इस राष्ट्रीय संकट के प्रश्न पर हमारी सरकार और हिन्दुस्तान के सभी विरोधी दल के नेताओं को कई दिन बहस कर के इसके लिए कोई एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश में जहां हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली से देश का शासन करने का निश्चय किया है प्रजातंत्र का चिराग तब तक नहीं जल सकता है जब तक कि टकराव की राजनीति का खात्मा नहीं होता । उन मुल्कों में जहां टकराव की राजनीति हुई वहां से प्रजातंत्र खत्म हो गया । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में 40 वर्षों से पंचायती राज कायम है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now. There are so many speakers.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में खत्म करूंगा । पंचायती राज के माध्यम से हम समस्याओं को हल करना चाहते हैं । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 40 वर्ष पहले हमारे देश का संविधान बनाने वाले लोगों ने फैसला किया कि दिल्ली की सरकार और प्रांतों की सरकारों के चुनाव समय पर कराए जाएं ।

मैं चाहता हूं कि देश की जनता की समस्याओं को हल करना है तो सारे भारत के राज्यों में ग्राम पंचायतों के चुनाव भी भारत के संविधान में संशोधन करके स्टेचयटरी अमेंडमेंट करने के बाद कराए जायें ताकि सभी जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार सभी कार्य कर सके । **आदरणीय उपसभापति महोदय:** . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No new point now, please.

श्री कल्पनाथ राय : *आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से, सरकार से कहना चाहता हूं कि सूखे के प्रश्न को, सूखे के वर्तमान संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों की एक कांफ्रेंस बुलाएं और प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाएं और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनका इस्तेमाल करके वर्तमान संकट को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें । क्योंकि हिन्दुस्तानी की जनता यह समझती है कि हमारे नेता हमारे दुखों में भाग लेने के लिये सिंसियर हैं तो वे एक रोटी खाकर भी, एक मुट्ठी चना खाकर भी अपने देश के इस संकट में सरकार का साथ देंगे और उसमें सरकार का हाथ बटाएंगे । आदरणीय रामानंद यादव जी और मकवाणा साहब से कहना चाहता हूं कि वे अकाल के इस गंभीर संकट को दूर करने के लिए तुरन्त प्रयास करें ताकि हमारी इस राष्ट्रीय समस्या का हल हो सके और देश के लोगों का इस गंभीर संकट से छुटकारा मिल सके । धन्यवाद ।*

SHRIMATI AMARJIT KAUR (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, the drought in my State of Punjab is so severe and unprecedented that I am afraid this season there will be a shortfall of the paddy crop up to the tune of 20 to 40 per cent. This is a massive loss to the farmer of Punjab, so much so, that the farmers will find it hard to put together their meagre resources to pay back their several loans and re-invest for their future crops. They have been put in a dilemma by the gods as to whether to plough their drying paddy fields and quickly sow alternative crops, or to wait for the rains. And all this, Sir, at what cost and consequences?

The situation in Punjab today is that the small and marginal farmers has lost his paddy crop. The ground water level has gone down 20 to 40 feet, necessitating all tube-wells owners to go through the added expense of re-boring their tube-wells at very deep levels. Open wells have all gone dry or are now so deep that the poor farmer now finds it too expensive to readjust the water-drawing system to irrigate his fields.

The Punjab Government, Sir, is at this stage, in no position today to financially tackle this huge task single-handedly by itself—what with all the recurring expenses involved in maintaining peace in the State. The situation, Sir, is clear that this most progressive State in India is being stripped naked by nature and human madness collectvely, and the Punjab Government can only save the situation with the active help of the Central Government. I, therefore, urge the Central Govvernment to urgently consider the following remedies to ease the situation in Punjab:

(1) To immediately declare Punjab a "Drought-hit" State.

(2) To immediately rush in experts of the ICAR and the IARI to help the experts of the Punjab Agricultural University to find an immediate solution for re-cropping farmers' fields and saving the tubewells going dry.

(3) Giving adequate financial aid to the Punjab Government to carry out immediate relief work to support the small and marginal farmers who have lost their crops.

(4) Magnanimous allotment of loans to small and marginal farmers for their future cropping patterns.

(5) Introducing crop insurance.

(6) The defferring of loans and interest payment of all agriculturists of Punjab.

(7) Increase rates of existing crops after harvest.

(8) Subsidise seed, fertiliser, weedicides and pesticides for re-cropping patterns for small and marginal farmers.

(9) Increase the inflow of canal waters into the State.

(10) Increase the inflow of power supply and ensure no diesel shortage in Punjab.

Thank you, Sir.

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् हमारे सम्मानित साथी कल्पनाथ राय ने बहुत बनियादी और सही बातें, जो सूखा है उसके सिलसिले में कहीं । मैं जब पढ़ता था उन दिनों डा० लोहिया का एक भाषण संसद में हुआ था वह पढ़ा था । सुबह के अखबार में कुछ मंत्रियों की तस्वीरें छपीं थी हंसते हुए तो लोहिया जी ने उस दिन पार्लियामेंट में सवाल किया था कि हंसने का सबब क्या है ? क्या ऐसी हालत है मुल्क की कि आपको रोज सवेरे देश के लोग हंसते हुए देखें । आज जिस प्रकार का सूखा है मैं बाकी चीजों को छोड़ देता हूं वह यहां कहना इरलिवेंट होगा, सूखा सिर्फ सूखा जो सरकार ने खुद माना है 80 साल के बाद इस तरह का सूखा पड़ा है उसको देखते हुए जो हमारी रोज की दिनचर्या है उसमें हम सबों की खासतौर से सरकार की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती कि देश के सबसे गरीब जो आदमी हैं उस पर इस सरकार का कोई असर पड़ रहा है या उसकी कोई संवेदनशील जिम्मेदारी है कोई काम हमारा यह नहीं दीखता कि हमारा रिश्ता उस आदमी के साथ है जो

[श्री सत्यपाल मलिक]

दूरदराज के गांव से जहां सूखा पड़ा है उससे सम्बन्ध रखता है जो सूखे को झेल रहा है। किसी काम में फर्क नहीं आया चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो चाहे भोपाल हो और चाहे चंढ़ीगढ़ हो। सूखे से कैसे लड़ा जायेगा इन सब चीजों पर मैं आऊंगा लेकिन एक सिम्बोलिक एक्शन हुआ करता है राज करने वाले लोगों का, जनता पर जिस वक्त आफत आती है उस वक्त उनके किसी काम से यह दिखना चाहिए कि कांटा चुभा हुआ है। जब देश पर संकट आता है नेताओं पर संकट आता है राज्य के जन नायकों पर संकट आता है तो बिना पढ़ा गरीब आदमी जिसने कभी यह नहीं जाना कि रेडियो कैसे चलता है जो गधा लेकर काम करता है, जो बैल लेकर काम करता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसा रिएक्ट करता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है लेकिन जब उस पर संकट आता है; उस पर परेशानी आती है तब हमारे किसी काम से यह फर्क नहीं पड़ता, उससे यह दिखाई नहीं देता कि हम उसके संकट में उसके साथ खड़े हैं। जो आप उपाय कर रहे हैं जो आपने गिनाया है वह तो करिये लेकिन कोई काम सिम्बोलिक दिल्ली में कर दीजिए जिससे यह लगे कि हम मुल्क की तकलीफ में उनके साथ हैं। आप यह काम तो कर ही सकते हैं इस पर एक पैसा खर्च नहीं होता कि जब तक बारिश नहीं होती, जब तक मुश्किल से, सूखे से निपटा नहीं जाता कम से कम सरकार के मंत्री और अफसर किसी दावत में नहीं जायेंगे और किसी फाइव स्टार होटल में किसी सरकारी सम्मेलन की दावत नहीं होगी। कोई खर्चा आपका नहीं होगा बल्कि बचेगा लेकिन मुल्क के लोग महसूस करेंगे कि दिल्ली में सूखे का असर हुआ है। कम से कम रोशनी बंद कर दीजिए जो सजावट बड़ी इमारतों पर रात भर होती है, सूनी सड़कों पर जलने वाली रोशनी है उनको यह कहकर बंद कर दीजिए कि सूखे का भारी संकट है इसके लिए हम आपके साथ हैं मैं यह तकलीफ के साथ बात कर रहा हूं। मैं लाइब्रेरी चला गया था सूखे की फाइल देखने के लिए। मैंने समझा यह हाल की फाइल होगी। देखा सूखा राजस्थान में है, सूखा महाराष्ट्र में है, तीसरा साल सूखे का गुजरात में है, चौथा साल राजस्थान में है सारी फाइल देखी 85 की 86 की और 87 की हम हर साल इसका विलाप करते हैं इस साल कुछ ज्यादा है सिवाय इसके कि इतनी राहत का पैसा वहां पहुंचा दिया और वह पैसा खर्च हो गया इस हालत से निपटने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। सारे देश में आर्थिक समीक्षा को पढ़ने के बाद और तमाम चीजें जो छपती हैं उनको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी सारी किस्मत इन्द्र देवता के कब्जे में है। हमारी जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं वे दस-दस साल पिछड़ चुकी हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं वे ली नहीं जा रही हैं। सिंचाई की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका जिक्र तो किताबों में आ जाता है लेकिन जो छोटी योजना हैं उनका तो कोई पता ही नहीं चलता है। जिला स्तर की छोटी योजनाएं बांध बनाने की योजनाएं तालाब बनाने की योजनाएं वाटर टैबल को ऊपर उठाने की योजना वे सारी योजनाएं देश में पड़ी हुई हैं। जो रुपया सूखे के काम के लिए जाता है वह बेचारे मजदूर को एक दिहाड़ी के काम के लिए दिया जाता है। उसका कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है। एक खतरनाक चीज और हो रही है। उत्तर भारत में सेल्फ इरीगेशन का एक सिस्टम है ट्यूबवैल का जो किसानों ने खुद खड़ा किया है। अंग्रेजों ने हमें नहरों का सिस्टम दिया जिनकी वजह से कुछ सस्टैनेन्स हो सका आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने साइंटिफिक विजन से ट्यूबवैल लगाने शुरू किये और जगह-जगह पर ट्यूबवैल लगे और किसानों ने चार फसलें लेनी शुरू कीं। लेकिन एक डिस्टर्विंग फेक्टर यह है कि सैल्फ इरीगेशन का सिस्टम पिछले पांच-सात साल से ठप्प पड़ गया है उसकी बढ़ोतरी रुक गई है। उसके कारण जानने की कोशिश की जानी चाहिए। अभी हालत यह है कि अगर सूखा पड़ जाता है या मानसून तीन हफ्ते के लिए डिले हो जाता है तो वाटर लेबल नीचे हो जाता है इस प्रकार से हमारा सैल्फ इरीगेशन का सिस्टम तहस-नहस हो गया है। हमारे देश में

जल का स्तर नीचे चला गया है । इसके कारण सैल्फ इरीगेशन का सिस्टम बंद हो चुका है।

पीने के पानी की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है । माइकल लिप्टन नामक एक विद्वान ने एक किताब लिखी है- व्हाई पुअर मैन स्टे पुअर? यह बहुत अच्छी किताब है। इसकी भमिका में वे लिखते हैं कि दुनिया में काले और गोरे की बहस बिलकुल फजूल है । असल में खतरनाक बायस यह है कि अरबन और रूरल का बायस सबसे बड़ा हो गया है । शहरों मे जो लोग सत्ता में हैं, व्यापार करते हैं ब्यूरोक्रेट हैं राजनीति में हैं उनको दिया जाने वाला पीने का पानी आप देख लीजिये और गांवों में जो पानी दिया जाता है उसको देख लीजिये । शहरों और कस्बों में रहने वाले 82 प्रतिशत लोगों को पीने के लायक अच्छा पानी दिया जाता है और गांवों में बसने वाले सिर्फ 13 सैकड़ा लोगों को पीने का पानी दिया गया जाता है पीने का पानी शहरों और गांव वालों के लिए जो मुहैया किया जाता है उसका एक तिहाई शहरों में चला जाता है और दो तिहाई ही सारे देश में फैले हुए गांवों में दिया जाता है। आज हमारे गांवों में हालत यह है कि हमारी मां-बहिनें पानी के घड़े ढोते-ढोते अपनी जिन्दगी गुजार देते हैं। एक बार श्री हुक्म देव नारायण यादव जी ने कहा था कि शहरों में रहने वाले लोग पेशाब का पानी बहाने लिए फ्लश से जो पानी बहा देते हैं उसका गांव वालों के लिए बहुत महत्व है। यह बात भले ही पढ़-लिखे और सम्भ्रांत कहे जाने वाले लोगों को क्रूर लगे लेकिन यह सही स्थिति है । गांव वालों को पता है है कि पानी का महत्व क्या है। यही - हालत राजस्थान के गांवों की है। हरियाणा के गांवों की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों की है । लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं दस दस कोस जाकर पानी मिलता है । आप टेन्कर से इंतजाम करते हैं लेकिन वह माकूल इंतजाम नहीं होता है। मवेशियों की हालत तो और भी बुरी है। व बचारे तो बोल भी नहीं सकते हैं। उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। राजस्थान के जसलमेर, नागोड़ जिलों में एक एक बछड़ा 20-20 हजार में बिकता था, उनको लोग तिलक लगाकर छोड़ देते हैं। यही हालत गुजरात की है। वहा पर खेड़ा संव कुछ काम कर रहा था जहां पर जानवरों को एक इलाके से दूसरे इलाके में भेज दिया जाता था। हर साल चारे की समस्या पैदा होती है। फोडर कारपोरेशन बनाने की बात भी कही जाती है । अगर चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो -. हमारा यह पशुधन बबाद हो जाएगा। चारे के बारे में, फसल के बारे में और अन्य कामों के लिए किसानों को दीक्षा देने की बात तो आप कीजिये लेकिन किसान- स्वयं अकलमंद है वह जानता है कि कब क्या करना चाहिए लेकिन इस वक्त उसकी लाचारी और मजबूरी है उसके सारे कर्जे लगान और बच्चों की फीस य सारी चीजें तत्काल माफ कर देनी चाहिए और जो कर्जे माफ नहीं हो सकते हों उनकी वसूली रोक देनी चाहिए। बिजली तथा जो लकड़ी के काम है जो औद्योगिक उत्पादन की चीजें है। ऐसी चीजें काटकर- आपको तत्काल गांव में पहुंचा देनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कृपया यह बतायें कि क्या कोई मानेटरिंग पिछले दो माह से हुआ है और उस मानेटरिंग के तहत केन्द्रीय सरकार ने क्या किया ? सबसे पहले आप कब जागे ? आपके बयान से लगता है कि 26 जुलाई को कुछ लोगों की मीटिंग थी । इसके पहले स्टेटस ने आपको कब कब लिखा और आपने कब कब स्टेटस को लिखा। इसको अगर आप जरा खुलासा कर दें तो हमारा स्पष्टीकरण हो जायेगा कि आप इस बारे में चेते हुये थे।

आखिर में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आप जो राहत का रुपया देते हैं, यह बहुत जरूरी है, जाना चाहिये, ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिये । लेकिन रुपया तो बादशाह भी बांटते थे डोल्स शाहजहां भी शनिवार के दिन बांटता था । उसमें सिर्फ सस्टीनेंस होता है । वह मिल गया और दो दिन का गरीब आदमी का खाना चल गया । कोई योजना ऐसी होनी चाहिये जिसमें सूखे में

[श्री सत्यपाल मलिक]

राहत का भी काम भी हो और उसके साथ साथ उसमें एक धनराशि ऐसी जो उस उस इलाके में ी जाय। ब्लाक लेबल पर बनाइये या ताल्लुका लेबल पर बनाइये लेकिन आपको एसी ोजनायें बनानी चाहिये कि तीन साल में राहत के लिये यह रुपया सस्टीनेंस में देंगे और यह रुपया वहां ऐसी योजनाओं में लगे जिससे अगली बार सूखे से निपटा जा सके। क्या स पर सरकार विचार करेगी यह आप बताने की कृपा करें? हर साल हम अरण्य-रोदन करते हैं लेकिन फिर भी यहीं बातें होती हैं और सरकार की तरफ से वही जवाब देते हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सिलसिले में आपने क्या काम किये हैं जो सस्टीनेंस से अलग हैं, जिनसे कोई चीज बनती है। जिससे पानी का इंतजाम हो सकता है। इस सिलसिले में मंत्री महोदय अपन जवाब में बताने की कृपा करें बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के प्रान्तों के जो नाम है उसमें राजस्थान का नाम पर्यायवाचिक रूप से सूखे और अकाल से जुड़ गया है। यह आज से नहीं यह सदियों से है। राजस्थान जो पहले राजपुताना था और उसका एक भाग जो मवाड़ था वहां के सभी निवासी यह कहते हुए चले गये हैं, हमारे सभी पूर्वज यह कहते हुए चले गये कि एक वर्षा हो जाये, एक वर्षा हो जाय और कभी भी उन्होंने अपनी जमीन की पूरी फसल नही उठाई। राजस्थान पर हमेशा दोहरी मार पड़ती है और यह इसलिये कि वहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और वहां पर मानसून की लुका छुपी इस प्रकार से होती है कि थोड़ी वर्षा होने पर जब पहली बार फसल बोई जाती है और फिर जब खतों को पानी की जरूरत होती है तो दूसरी बार की वर्षा का अंतराल इतना अधिक होता है कि कि तब तक बोई हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस अंतराल के बाद जो दूसरी बरसात होती है तो उस समय यह महसूस किया जाता है कि अब तो फिर तीसरी बरसात होगी और अगर हम धान बो दें तो हमारी धान की फसल हो जायेगी। लेकिन वह बरसात जब हो तब हो तब तक किसान का दूसरी बार का धान फिर खराब हो जाता है और तीसरी वर्षा के अभाव में दूसरी बार का का बोया हुआ धान नष्ट हो जाता है। इस तरह से किसानों को डबल नुकसान उठाना पड़ता है। महोदय, यह अकाल इस शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल है। राजस्थान के लोग इसके आदी हो चुके है। वह से झेलने के आदी हो चुके हैं। वह इसको तो झेल रहे हैं। लेकिन गंभीर स्थिति का इस बात से पता लगाता है है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो राज्य पानी के घर है वहां के माननीय सदस्य भी स समय जिस आवाज में बोल रहे हैं इस सदन में उससे पता लग सकता है कि राजस्थान की कितनी गम्भीर समस्या होगी जो कि लगातार पिछले पांच सालों से इस अकाल की चपेट में है। अभी एक दो दिन पहले जब माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था। मैंने जब यह जिक्र किया था तो मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान को पांच लाख टन धान दिया। मंत्री जी देखिए राजस्थान को अपने पांच लाख टन दिया लेकिन सके पहले कई साल तक अकाल चलता रहा तो आपने क्या दिया? इसको आप देखें पांच लाख टन के लिए आपने कह दिया पिछली बार भी पांच लाख टन कहा था लेकिन दो लाख टन पहुंचा तीन लाख टन नहीं पहुंचा। फिर बाद में कह देना पड़ेगा। उस स्थिति को देख कर राजस्थान पर नजर डालिये राजस्थान दोहरी मार खा रहा है एक तो रेगिस्थान है और दूसरा वहां पर अरावली पर्वत है जो कि पहाड़ी इलाके है। आप पहाड़ी इलाके को विशेष महत्व देते हुए विशेष अनुदान देते हैं और राजस्थान रेगिस्तान होने के कारण भी विशेष अनुदान प्राप्त करने का हकदार है ऐसी स्थिति में पहाड़ी इलाके और रेगिस्तान के इलाके को देखते हुए इसको अन्य प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा अनुदान देने की आवश्यकता है। इस पर इस दृष्टि से आप

विचार करियेगा आपने स्वयं भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि 35 मेटीरियोलोजिकल-सब डिवीजनों में इस साल 10 में बरसात हुई है और वह भी क्या असर कर रही है हिन्दुस्तान की इकानोमी पर। हमारे हिन्दुस्तान में एक सब से बड़ी विडम्बना यह भी है कि एक तरफ तो पानी की आधिकता के कारण बाढ़ के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है दूसरी तरफ पानी के अभाव के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है। 10 मेटीरियोलोजिकल डिविजन्स में बरसात होने पर भी हिन्दुस्तान की इकोनोमी पर कोई बढ़ोत्तरी हो रही हो ऐसी बात नहीं है। यह सब से भारी महाकाल जो पड़ा है इसमें हमारे प्रधान-मंत्री ने बड़ी सूझबूझ से समय पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन स्वयं की अध्यक्षता में किया है उससे जनता को एक आशा बंधी है कि जरूर इस गम्भीर समस्या के समय जनता को राहत मिलेगी और काम होगा। भारत की आबादी का 75 प्रतिशत गावों में रहता है उनका मुख्य काम भी खेती है इसलिए हम को उसी प्रकार की प्राथमिकताएं भी तय करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए देखना पड़ेगा कि इस 75 प्रतिशत आबादी के लिए हमें किस ओर ज्यादा अग्रसर होना पड़गा राजस्थान में राजस्थान कनाल जिसको इन्दिरा गांधी केनाल परियोजना कहा जाता है पिछले 25-30 साल से उसकी लागत दूगुनी तिगुनी हो हो चुकी है। अगर समय पर यह पूरी हो जाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अकेला राजस्थान आने वाले 25 सालों में पूरे हिन्दुस्तान का पेट भर देगा। यह एक वास्तविकता है। यदि उस बंजर भूमि पर पानी के थोड़े से छींटे पड़ जायें तो यह इतनी उपजाऊ भूमि है कि वहां पर उपज हो जाती है। राजस्थान में यदि पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो यह राजस्थान ही पूरे हिन्दुस्तान का पेट भर देगा। माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर योजना के माध्यम से जरूर पूरी धनराशि देने की कृपा करें। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी केन्द्रित करना चाहूंगा कि अभी एक स्टार्ड कवश्चन के जवाब में आपने जो आकड़े दिये है उनके अनुसार 9 राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता मांगी गई है वर्ष 1986-87 के लिए। उन 9 राज्यों में राजस्थान की ओर से 781.83 करोड़ की मांग है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में सब से अधिक माग राजस्थान द्वारा की गई है। आन्ध्र प्रदेश ने केवल 240 करोड़ ही मांगे गुजरात ने 429 करोड़, कर्नाटक ने केवल 11 करोड़ मांगें केरल ने 281 करोड़, मध्य प्रदेश ने 75 करोड़ महाराष्ट्र ने 453 करोड़ और तमिलनाडु ने 348 करोड़ तथा गोआ ने 10 करोड़ की मांग की है। इस लिस्ट को देख कर भी आपको यह महसूस करना पड़ेगा कि धनराशि का आबंटन करने के लिए जो सीलिंग लगा दी है। उनकी छाप पड़ी है। तमिलनाडु में भी राजस्थान एसोसियेशन चाहे शिक्षा के काम हो चाहे स्वास्थ्य के एक करोड़ की सहायता से उनको चला रही है। इसलिए राजस्थान इस मामले में बहुत आगे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव अपनी ओर से निवेदित करना चाहूंगा एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत लेवर अगर मिलिट्री की तरफ से लगा कर काम करवाया जाये तो समय आगे लगाना है वह बिल्कुल कम हो जायेगा। यह नहर योजना पूरी हो जायेगी। जब तक केवल लोकल लेबर फोर्स के आधार पर चला जायेगा तो इसी प्रकार से यह काम लम्बे समय तक चलता रहेगा। हालांकि सतह का पानी बहुत नीचे चला गया है फिर भी जो हैंड पम्पस है उनसे लोगों को दिल में थोड़ा सा आश्वासन रहता है कि हां रात बिरात जाकर थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे लेकिन इस तरह के हैंड पम्पों की मात्रा दुगनी तिगुनी करनी पड़ेगी इसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। कूंए जो है किसान अपने पैसों से उनको गहरा नहीं करा सकते हैं। जब तक पूरा अनुदान न दिया जाये गहरा नहीं करा पायेंगे इससे पीने के पानी की समस्या और मवेशियों को पानी देने

[श्री सत्यपाल मलिक]

की समस्या हल नहीं हो पायेगी। किसानों का ऋण है उसको स्थगित किया जाये और आने वाली फसल के लिये अनाज वगैरह दिया जाये। ये काम आपको करने होंगे।

मैं तीन चार मुख्य सुझाव देना चाहूंगा। जिस प्रकार आजकल टी० वी० वगैरह पर 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के से नीचे की शादी न हो यह बराबर दिखाया जाता है। अधिक धनराशि का निर्धारण करना राजस्थान के लिये कोई एक अहसान नहीं हो। यह स वास्तविकता को आप देखेंगे कि राजस्थान पिछले 5 साल से अकाल से पीड़ित है और आपके द्वारा राहत दिये जाने की आवश्यकता है। जो राहत देने की प्रक्रिया केन्द्र की ओर से निर्धारित की गयी है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति देखते हुए राशि अलाट की जाती है। लेकिन राजस्थान बहुत लम्बा चौड़ा एरिया है जिसमें आबादी तो कम है एरिया ज्यादा है। आप असिस्टेंस आदमियों के हिसाब से देते हैं तो इस प्रान्त का भविष्य किस प्रकार से उज्जवल हो पायेगा, किस प्रकार से दूसरे प्रांतों के मुकाबले आ पायेगा इस ओर आपको देखने की आवश्यकता है। यह धनराशि केवल मानवों की जितनी संख्या है उसके आधार पर न दे करके एरिये के हिसाब से भी धनराशि को आपको एड करना चाहिये।

मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक मनुष्यों के जीवित रहने का सवाल है तो फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के माध्यम से मनुष्य खाने पीने के मामले में जीवित रह पायेगा लेकिन बेचारा अनबोल जानवर घास के बिना इस अकाल की स्थिति में क्या करेगा क्योंकि केवल रेत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है इस स्थिति में जब तक आप फोडर कारपोरेशन आफ इण्डिया नहीं बनायेंगे तो स्थिति को झेलना बड़ा ही दर्लभ होगा। राजस्थान में यह बहुत कम होता है।

आप स्वयं जानते हैं जब आप जोधपुर जा रहे थे कि जो राजस्थान के निवासी हैं वे बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं मारवाड़ी अकाल राहत के माध्यम से अभी करोड़ों रूपये का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है यह एक मिसाल है और सरकार के साथ सहयोग है प्रधान मंत्री जी के आवाहन पर स्वयंसेवी संस्थायें आगे आयी हैं जनसमस्याओं के निवारण में राजस्थान अग्रगणी है हालांकि पिछड़े मुल्कों में है राजस्थानी अपने जीवनोपार्जन के लिये हिन्दुस्तान के चारों कोनों में गये हैं और हर जगह

4-00 P.M.

उपसभाध्यक्ष श्री जगेश देसाई): और जोर से चलता है।

श्री भंवर लाल शर्मा: हो, तो इस तरह से मानस बनता है लोगों का जिस प्रकार से पोलियो के इन्जैक्शन लगाने का भी बड़ा चला रहा है, तो इसी प्रकार से टी०वी० के माध्यम से पानी की खपत कम कसे की जाये, इस ओर भी जन-मानस बनाने की आवश्यकता है। इसका भी टी०वी० पर प्रदशन करने की आवश्यकता है ताकि पानी की खपत कम हो जाये और साथ ही ड्राई-फार्मिंग कैसे हो, राजस्थान मध्य प्रदेश वाले इलाकों में सका बहुत ही किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। वैसा भी टी०वी० के माध्यम से प्रचार करवाया जाये।

राजस्थान के बारे में अब तक कहते रहे हैं कि जब कभी अकाल पड़ता है, तो मालवा की ओर भागते हैं, और मवेशी भी मालवा जाते हैं और मनुष्य भी मालवा जाते हैं, लेकिन मालवा भी इस बार स्वयं अकाल से पीड़ित है। तो वहां भी पलायन होना बड़ा मुश्किल होगा। ..... (**व्यवधान**)

अब फाडर के लिये भी मैं कुछ माननीय मकवाना जी से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने कुछ ऐसे नियम बनाये हैं कि आपको पंजाब से ही अगर घास आती है तो अनुदान देंगे इसके अलावा कहीं से घास आएगा तो नहीं।

तो मारवाड़ा ने भी शिकायत की थी पिछली बार जब मैं गया

उस समय, वरना हम बिल पास नहीं करेंगे । तो इस प्रकार से वहां का घास राजस्थान के लिये भी उपयोगी नहीं हो पा रहा है । मवेशियों के लिये खाने के लिये नहीं है।

तो ऐसी कोई अगर वहां रोक हो, तो वह भी आप दूर करिएगा ताकि उसका पेमेंट हो सके और जसा कि आप ने स्वयं माना है, पिछले तीन-चार साल से कि राजस्थान के 27 जिलों में से 1985-86 में 26 और 1986-87 में पूरे 27 के 27 और इस साल भी 27 के 27 जिलों में आज अकाल की स्थिति पूरे गांव कोई 38 हजार गांवों में करीब 38 हजार ही प्रभावित हैं, पिछले साल 21 हजार प्रभावित थे और पूरे सवा तीन लाख मवेशी इससे प्रभावित हैं और राजस्थान के लोगों के लिये पशुधन ही जो उनका केवल एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन है वह समाप्त हो जाएगा, जो हरित क्रांति तो आ गई, लेकिन श्वेत क्रांति यह भी समाप्त हो जाएगी और कुछ नहीं रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, Mr. Marayarasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for having given me this opportunity to speak on the drought situation in that country.

Sir, the honourable Minister, considering the fact that there is monsoon failure in the country and the entire country is in the grip of drought, came out with a *suo moto* statement in this House a few days back and our honourable Prime Minister also, considering that there is a drought situation prevailing in the country, has appointed under his chairmanship a Cabinet Committee for the purpose of looking after the relief measures in the drought-affected areas.

Sir, the present drought is not actually confined only to the Congress (I)-ruled States. It is uniformly spread and it is prevalent even in the Opposition-ruled States like Karnataka and Andhra Pradesh and in the States where the Congress (I) is in power. Therefore, for the relief measures which have been undertaken by the States to meet the drought situation, they are mainly relying upon the Central assistance because the funds provided by them under 20-Point Programme and also for the Drought-Prone Area Programme at the block level are not sufficient and with these funds they are not in a position to meet the present unprecedented drought which is prevailing in this country after thirty years. Now, Sir, the present Session of Parliament, which is called the Monsoon Session, can very well be called the Summer Session because in Delhi we have not been able to get rains till today, till the first week of August. The States which are affected mostly are Rajasthan, part of Punjab, Maharashtra, Bihar and Gujarat . Only two States which have plenty of rain are Goa and Assam. In Assam we have floods. Bengal also is affected. In the south in all the States, except some part of Kerala, drought situation is prevailing. Now the Government is faced with the problem of how to preserve water. Even if there is rain in particular areas, their main problem is to store water There is drinking water supply problem in the villages and also in the urban areas. In most cities like Madras and others drinking water supply is made to the people twice in a week, and that too for a limited period. The areas which are by the side of sea-shore are getting drinking water supply and the Government is providing for them. But in most of the areas the ground water potential has gone down up to 100 feet or 200 feet, especially in areas of Rajasthan and Bihar. Therefore, the main crops which they have been raising in the Punjab Gujarat, Orissa and other places—paddy, sugarcane and groundnut—are affected. Largely our country comprises small farmers and marginal farmers. Big land-

[Shri V. Narayanaswamy]

lords comprise not even 7 per cent. But nearly 90 per cent of the population has been affected by drought. Now, the remedial measures which the hon. Minister, while making the statement, has listed are storing water provided to the agricultural lands, deepening wells, making use of ground water potential and giving variety seeds to farmers to start their cultivation. Sir, I would like to say that even if the monsoon fails and there is expected to be rain in the northern part of the country, short-duration crops can be raised, so that the farmer who has raised crops for a period of six months can raise crops of three months. Therefore, the agricultural production to a certain extent can be increased.

Sir, about one thing we are sure. We have abundant food supplies. Even though the drought situation is there, we can manage the situation. But if there is acute drought, the food supplies which we have now will definitely be depleted and we may not be able to store food stocks for the coming year. Therefore, it is not a question of short-term measures. I would like to say that the Government should have a national policy on irrigation so that there is inter-connecting of important places where agricultural operations are being carried out and connecting the rivers and canals throughout the country. There should be a master plan for that, so that even if there is drought in one State water supply is provided by the State which has excess of it. Therefore, I would like to say that there should be coordination between the Ministries. This can be achieved if there is coordination between the Agriculture Ministry and the Ministry of Water Resources. Though it is a long-term process, it will be a permanent solution for giving relief to the drought-affected areas. During floods we find that the entire crop is washed away. During drought we cannot get any yield from the field. The person affected is the agriculturist. In the Southern States, the agriculturists are mainly dependent on ground water potential. Cauvery water dispute is getting prolonged. It should be settled soon. There is drought situation even in Pondicherry. Since the agreement was not honoured by the Karnataka Government, the States of Tamil Nadu and Pondicherry are suffering. We cannot raise any crop in that area. The agreement which has been entered into by the State Governments should be honoured by the State Governments. Whenever there is any dispute between the State Governments relating to sharing of water, the Central Government should intervene.

Apart from the drinking water problem, there is scarcity of fodder for the cattle. The cattle have been migrating from the areas where there is drought to areas where there is some water available. There is tension among the agriculturists because of migration of cattle. Therefore, adequate supply of fodder should be arranged to avoid these feuds. Whenever there is any request from States like Rajasthan and Gujarat, fodder should be supplied. Gujarat is having drought for the last 3 years. The Centre should see that fodder is supplied to these States. It is the duty of the Central Government to help them.

Whenever there is a request from the States, the Central Team goes there to find out the extent of drought and they provide funds to the extent available. But I find that when funds are provided by the Central Government for relief measures, they are not fully utilised. The funds are diverted for other purposes and projects in order to get popularity among the people, thus completely neglecting the relief measures. Therefore, there should be a monitoring agency of the Centre to find out whether the State Governments have spent the funds properly for the purpose for which they have been given. It is very important because the State Governments sometimes divert the funds for some other purposes. The Centre should take note of it and implement it.

There is another important thing which the Central Government should do. They should provide assistance for deepening the bore wells and wells. There is ground water potential available in some areas. But the water level has gone down. The

agriculturists will be able to get water supply if the bore wells are deepened. The Government should give the subsidy. The subsidy which is given at present is very meagre. The subsidy should be at least 75 per cent of the project. At present, the State Government give subsidy to the extent of 30 or 40 per cent for the purpose of repairs of bore wells. I would request that the Central Government and the State Governments that they should work in a co-ordinated manner and they should take steps for the purpose of helping the farmers because the rural population is the basis of the development of our economy.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka): Mr. Vice-Chairman ,Sir, I am not going to refer to all the suffering of human beings and animals because all that has been narrated by other Hon. Members who have spoken before me. Sir, it is an irony that in the entire eastern India there are floods. These floods are very severe especially in Assam, West Bengal and other parts of eastern India. On the other hand, drought has taken a severe grip in southern India and western India and some parts of northern India. There may be some pockets in these States where there may be some rains, but, by and large all around the country there is the natural calamity of drought. Nobody is responsible for this situation. But we will have to tackle this problem. How we will have to tackle this problem, for that we will have to suggest remedial measures. If I too repeat the same things that we will have to make a provision for drinking water and fodder, it is not going to solve the problem.

Sir, I belong to Karnataka. In Karnataka, out of 19 districts, in 17 districts there is drought. The rains should have started long back. But, unfortunately, for the last three months there have been no rains. And this situation has been occurring for the last five years. And the State Government is experiencing great difficulty in providing relief to the people. No doubt, the Central Government is providing relief by giving funds. I will come to that aspect later on. But how are those funds being utilised. There are places where there used to be 75 inches or 80 inches rain, just like Coorg or the catchment area of Cauvery. There are no rains in those parts and there is no water in Krishnasagar. If you see today's "Hindu," you will know that there is no water in Krishnasagar. Actually the position is that in the month of July it used to overflow and the authorities used to discharge the water and it used to go to Cauvery and then to the people of Tamil Nadu. But unfortunately there are no rains and the people of Karnataka are themselves experiencing difficulty to get drinking water. One or two of my friends from Tamil Nadu commented that Karnataka is not releasing water. Even my friend just now said that we are not adhering to the agreement which has been entered into in 1924. What kind of an agreement is it? This is an agreement which has been entered into between two unequal parties. On the one hand, there were the British and, on the other hand, there was the Maharaja of Mysore, who was a very small man. And, if you go through the terms of the agreement, they are more favourable to Tamil Nadu than to Mysore Maharaja. This agreement is not entered into between the people of Karnataka and the people of Tamil Nadu. Therefore, we are not bound by, and we are not going to abide by, that kind of an agreement which was entered into between two unequal parties and we are not going to implement that agreement. Therefore, my submission is that there is no point in Tamil Nadu raising the question that they are not getting water from Karnataka on the basis of the agreement. We are not adhering to that agreement. We are not a party to that agreement.

SHRI V. NARAYANASAMY: Therefore I say the Central Government should interfere.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Even for that there are some rules. The Centre can interfere only on the basis of some rules. Sir, I will come to a basic point.

Now, everybody is asking for money from the Centre. I do not know whether

[Shri Veershetty Moglappa Kushnoor]

they are aware or not, the Centre is not going to give a charity from its own exchequer. What they are giving is from the Plan funds. It is being given by way of an advance from Plan funds. Most of the States which are suffering for the last five months are using this money for this kind of relief work. It is not meant for that. Therefore, my submission is that this relief which is being given by the Centre, it should also be treated as a grant as it is given in flood hit areas, where 75 per cent is given as a grant. Whereas here only 25 per cent is given as a grant. and the rest of that the States will have to provide and they will have to spend from their own plan funds. What is happening due to this situation? If you see the financial position of the States, especially Karnataka, you will find that the State has become bankrupt. There is no money. Even the cheques are bounced and they ask the treasury not to issue cheques, and even if they sanction an amount, they do not issue cheques for months together. Why is it happening? It is because most of the Plan and non-Plan funds are being utilised for cheap publicity and on sarees and dhotis. So, whatever amount for drought relief is released from the Centre, its proper utilisation must be monitored. My submission is that most of the funds given to Karnataka is misutilised. And I say this with all the responsibility that the amount of Rs. 34 crores given to Karnataka Government as Central subsidy has been misutilised. The entrepreneurs are not getting any help. And even the present release, I believe, is being misutilised and has not been spent for the purpose it is taken. Therefore, my suggestion is that while specific amounts are released by the Centre, the M.Ps and M.L.As should monitor the expenditure of that money which is given by the Centre to the State for specific relief purposes. At the district level also it should be monitored. We will have to tackle this problem of drought on a war footing. The Prime Minister has been siezed of this problem and he has already appointed a Cabinet Group for the purpose. But my submission is that when we know that two-thirds of the States in the counry are under the grip of drought, there must be a committee under the Chairmanship of the Prime Minister, and the Chief Minister of the concerned State should be a member and they should try to tackle the problem of drought. This must be a high-level committee. Similarly, in the drought-affected States, the Chief Minister of the State and the leader of the opposition must be members of that committee and also the Minisers holding key portfolios should be its members at the State level. At the district level again, the Members of Parliament should be involved. The Member of Lok Sabha from that State should be the Chairman of the district-level committee together with M.L.As as its members, and also the District Collector should be there and they should monitor the entire work concerning drought relief measures, problem of drinking water, fodder problem and all these things can be tackled by such a committee.

This is not the first year of this problem. For the last 40 years we have been seeing these drought conditions. Therefore, all the expenditure which is being incurred to tackle drought situation must be borne by the national exchequer, and not by the State exchequer, because this is not a calamity created by the State; it is a natural calamly...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): And also not by the Centre.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: It is a natural calamity. I say this because the resources of the States are not adequate. So, the national exchequer should bear this expenditure. This is my suggestion. States don't have adequate resources and therefore, the Centre will have to bear it.

These are the points that I wanted to raise. I conclude.

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज देश के काफी भागों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। किसानों की, मजदूरों की क्या दशा

है, यह वही भुक्तभोगी जानता है असली तरीके से जो उनके बीच में रहता है। जो खुद किसान है, वह ज्यादा अच्छी तरह उसकी दशा को बता सकता है।

श्रीमन, उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में से 50 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश की 84 लाख 12 हजार हैक्टेयर जमीन में से 31 लाख 24 हजार हैक्टेयर जमीन की ही सिंचाई हो पाई है। इसके अलावा जो जमीन है वह बोयी नहीं गई है। यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश के किसानों को फेस करनी पड़ रही है। गांव में जब जाकर स्थिति को देखा जाता है, खेत के ऊपर जा कर जब किसान घूमता है तो उसकी फसल मिकुड़ी ई दिखाई देती है तो उसके दिल पर क्या बीतता है यह आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे यह ऐसा दृश्य है जिसकी कल्पना करके उस बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि जो फसल बो दी गयी है वह सूख गयी है 90 परसेंट उसका नुकसान हो चुका है। जो जमीन थी वह खाली पड़ी हुई है। वह खरीफ की फसल बो नहीं पाया, 100 फीसदी उसकी फसल का नुकसान हो चुका है। जो उसकी ईख की फसल है उसको देख कर रोना आता है। यह तो स्थिति फसल की रही। उसको कुएं में पानी नहीं मिलता, नलों का पानी सूख गया है। यह स्थिति पीने के पानी की हो गयी है। खासतौर से वहां पर जहां पर पानी नहीं पड़ा। जरा थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि जहां पीने का पानी न हो, फसल समाप्त हो गयी हो, वे बेचारे जानवर जो बोल नहीं सकते उसके लिए चारा भी न हो तो क्या स्थिति उस गांव की होगी। जो केवल मजदूरी करके, खेतिहर मजदूरी के रूप में वहां रहते हैं, जब किसानों की हालत यह है तो उन बेचारों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है? वह वहां से पलायन कर रहे हैं और शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों की अपनी क्षमता होती है कि कितने मजदूरों को झेल सकता है, कितनों को रोटी दे सकता है। सब लोगों को शहर रोटी देने में सामर्थ्य नहीं है। उस मजदूर की पत्नी जो जानवरों से दूध निकालती थी, खासतौर से जंगलों से घास काटकर उन जानवरों को खिलाती थी फिर दूध निकालती थी, वह घास न होने की वजह से वे जानवर मरने की स्थिति में है। उस दूध को बेच कर मजदूर की पत्नी को जो रोटी मिलती थी वह रोटी भी उस को नहीं मिल रही है। इस तरह से गांव में एक ऐसी दयनीय दशा हो गयी है जिसकी कल्पना करते ही परेशानी महसूस होती है।

मुझे तो अफसोस उन लोगों पर होता है जो भविष्यवाणी कर रहे थे मौसम विभाग के लोग कि अब बारिश आने वाली है, अब बारिश होने वाली है' मैंने भी अखबारों में पढ़ा था लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई। हम देखते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश आ जाया करती थी लेकिन अगस्त के प्रथम सप्ताह में मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन अभी तक मानसून दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे कब आयेगी इन लोगों के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता लेकिन भगवान ही जाने कब इस विपदा को टालेगा। जब तक मानसून नहीं आयेगी, पूरी तरह से राहत उसको नहीं मिल जायेगी, किसान की कठिनाई दूर नहीं हो पायेगी ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ज्यादा न कहकर कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत से मेरे भाइयों ने अपनी बात कही है लेकिन उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आप लगान की मुलतवी कर दें। उस किसान का लगान माफ कर दें। क्योंकि वह किसान लगान देने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए उस किसान का लगान माफ कर दीजिए। किसान को नई फसल बोने के लिए धन दिलाने की व्यवस्था करें। किसानों को खाद, बीज, पेस्टीसाइड्स वगैरह जो मूल्य आपने गरीब लोगों के लिए रखा है उसी राहत मूल्य पर उनको ये चीजें दी जायें। उनको ये चीजें इस तरह से सुलभ करायें कि जिससे आगे बरसात होने पर, सिंचाई की सुविधा होने पर फसल बोयी जा सके। वह ऐसा महसूस करें कि भारत सरकार ने हमें राहत दी है। इससे वे अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करेंगे।

आज की तारीख में बिजली आपके पास लिमिटेड मात्रा में है और इस हिसाब

[श्री घनश्याम सिंह]

से किसानों को इतना हिस्सा नहीं मिल पाता जिससे वे अपनी फसल को बो सकें। मैं चाहूंगा कि इस विपदा के समय पर भले ही आप और जगह से बिजली काट दें लेकिन किसानों को बिजली अवश्य दें जिससे वह फसल बो सकें और फसल की तैयारी कर सकें। जो हमारे मजदूर है उनको कार्य के लिए एन0आर0ई0पी0 में काम के बदले अनाज दिया जाना चाहिए और अन्य ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि किसानों को राहत मिल सके। मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि उनको दो जून की रोटी मिल सके। फ्री बोरिंग की सुविधा आपने दी है। जो किसान अपने साधनों से बोरिंग नहीं कर सकते हैं उनको इससे सुविधा हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप और अधिक धन आवंटित करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को पानी मिल सके, वे अपने पम्पिंग सेट लगा सकें।

आपने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था भी की है और इसके लिए नल लगाये हैं। लेकिन ये नल और अधिक लगाये जाने चाहिए ताकि सभी गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ऐसी सूख की स्थिति के वक्त इन नलों का महत्व है। इसी प्रकार से गांवों में चारे की कोई व्यवस्था नहीं होती है। निरीह पशु कुछ बोल नहीं पाता है। पशुधन को बचाने केलिए गांवों में चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांवों के चरागाह सूख चुके हैं। जिन जंगलों में आप पशुओं के चरने के लिए नहीं जाने देते हैं, ऐसे सूखे के अवसर पर आप पशुओं को वहां चरने की आज्ञा दें। यह तो नहीं होना चाहिए कि वे जंगलों को नष्ट करें, लेकिन चरने की आज्ञा दी जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन चला सकें। मकवाणा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिन स्थानों में वे अभी तक चारे की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं वहां पर इसकी व्यवस्था करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हुं कि जब सूखा पड़ता है तो केन्द्र से टीम जाती है और वह टीम आकलन करती है। उसके बाद वे राहत पहुंचाते हैं। इसमें दो तीन महीनों का समय लग जाता है। मेरा निवेदन यह है कि आप अपनी टीम अवश्य भेजें, लेकिन जब सूखा पड़े तो तुरन्त राहत कार्य के लिए सहायता दी जानी चाहिए। दैवी विपत्ति के समय इस प्रकार की सहायता की तुरन्त आवश्यकता होती है। इसलिए आप कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि सूखा पड़ने पर तुरन्त सहायता पहुंचाई जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सौ करोड़ रूपयों की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई है। यह बात हमने अखबारों में पढ़ी है। मेरा आपसे अनरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह सौ करोड़ रूपये मांगे हैं, वे आप तुरन्त उनको दें। अन्य राज्यों में भी सूखे की स्थिति है, राजस्थान राजस्थान मे है और अन्य स्थानों में है, वहां पर भी सूखे के कारण काफी तकलीफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो यह मांग है, उसको तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा न होने के कारण बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वे कुछ करें और आज यहीं पर कुछ ऐसी घोषणा करें कि मजदूरों और किसानों को लगे कि उनके लि[illegible] कुछ करने जा रही है और जो निरीह पशु हैं उनकी सहायता के लिए भी कुछ किया जा सके। अगर वे इस प्रकार की कोई घोषणा करेंगे तो किसानों और मजदूरों को भी लगेगा कि भारत सरकार उनकी मदद करने के लिए खड़ी है, अन्यथा हमारे किसानों और मजदूरों को कोई लाभ पहुंचाने वाला नहीं है।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Mr. Vice-Chairman, Sir, 20 hon. Members have participated in this debate, but when I look around, I find hardly ten Members present here. Many of them have raised a number of issues and they wanted me to reply. I was under the impression that at least they will be present to hear me

on the points which they have raised. But I am sorry to say that the interest which they took in speaking and debating the issues, is not visible in hearing the reply. Today one thing more I have noticed. This House has today really behaved as a Council of States, because all the Members who participated in this debate have pleaded for their respective States only. Keeping the situation prevailing in their State in view, they have pleaded very well the case of their State. That also shows that he States have briefed them properly.

A number of Members have made suggestions and requested that their State Governments should be helped and helped to the extent requested for. But you know the problem is very big and it is very easy to say that the Government of India should reimburse all the amount which the State Government has spent over the relief measures, or help in every matter which the State Government is supposed to do. This is not possible because the resources are limited with the Government of India also. Therefore, within those limited resources, we have to help the State Governments. Later in my speech, I will give you figures to substantiate my argument and to show how much the Government of India has helped the States and how much money the States have demanded.

This year it is really a very bad monsoon. The onset of monsoon was delayed by two days in Kerala, 21 days in the Eastern States and 28 days in Western U.P., Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Monsoon even though set in delayed has been weak and its advance has been slow, erratic and truant. This has affected very badly the crops. Out of 407 districts for which we have the reported rainfall data, the rainfall has been normal only in 145 districts, deficient in 110 districts and scanty or no rain in 152 districts. This shows the gravity of the situation. Not only this, five States were affected by drought for three years in a row. That is, for the last three years, they have been suffering from drought, though the number of districts affected in these States varied from year to year. Eight States received Central assistance for two of the three years. Only eight States had drought in one year only out of the last three years.

Coming to the floods, as many as 15 States received Central assistance for flood relief for three successive years. Four States received assistance for flood relief in two of these three years. Only five States received Central assistance for flood relief only for one year, that is, out of these three years. This is the position of the monsoon and this is the gravity of the situation because there are a number of States which have been suffering from drought and flood also for two, three years.

This year the monsoon can be compared only with the monsoon of 1965, which was the worst year. Both have normal rainfall in 10 out of 35 meteorological sub-divisions at the end of July. I have the figure of 29th July 1987, and on this date in 1965 also, 10 meteorological sub-divisions got normal rain. Rest of them were having scanty or deficient rainfall. But there is a difference between 1965 and 1987. Though it seems that the situation is similar in both the years and one may be led to believe that the position will be like that of 1965, that is not the case because in 1965 we had only 30.9 million hectares under irrigation. As against that, now we have 62 million hectares under irrigation. That is something more than double. Also the food situation prevailing in 1965 and prevailing today is not the same. Today we have 23 million tonnes of foodgrains as bufferstock, which was not there in 1965. This is the difference between the two worst years of this century.

However, it is very early to predict and forecast about the production of foodgrains. We do not know how the monsoon will behave in the coming days and, if it behaves well and if there is a good monsoon during the next two, three weeks, then there is a good prospect for the *rabi* crop, because the moisture will be there and with the retention of the moisture there will be a good *rabi* crop. So, it is very difficult at present, as I said, to forecast about production losses in foodgrains, oilseeds and other crops.

[Shri Yogendra Makwana]

However, 58 per cent of the total foodgrains comes from the *kharif* crops and 55 per cent of the total oilseeds are produced during the *kharif* season. These have been the worst affected--58 per cent of foodgrains and 55 per cent of oilseeds. The main crops, particularly of the *kharif* season, are rice, coarse grains, pulses, groundnut, soya bean, sesamum, etc. Now these are the crops affected badly. If I can say in terms of percentage, then rice is affected to the tune of 31.5 per cent--the unsatisfactory status of rice is 31.5 per cent. In coarse cereals it is 50.2 per cent and in pulses it is 33.5 per cent. Oilseeds are badly affected and groundnut is the worst-affected crop. The major groundnut-producing area is Saurashtra in Gujarat, and hardly 25 per cent of the farmers have sown the crop. The farmars wanted to retain their precious seed instead of wasting it. Therefore, they have not sown it. Only 25 per cent of the farmers have sown it. Another area is Andhra where a little bit good situation is prevailing. Even then, groundnut is the worst affected crop of this year, and unsatisfactory status is to the tune of 64.5 per cent; soyabean, 16.3 per cent and sesamum, 45.3 per cent. Sir, this is the situation so far as the major crops of kharif season are concerned.

Therefore, I am one with the hon. Members that it is a very difficult year for all of us, for the nation, for the farmers, and Government of India and the State Governments have to take all necessary precautions not only to provide foodgrains but also, as rightly mentioned by the hon. Members, drinking water and fodder to our animals. We have to preserve our animal wealth also. Government of India is aware of it. We have taken a number of steps, and we are going to a take a number of steps in order to meet the situation.

Sir, the position in the reservoirs is also not good. I have a report from the Ministry of Water Resources here, and it says that a quick analysis of the available data of July, 1987 indicates that overall position with regard to live storage in 47 important reservoirs monitored in the Central Water Commission, is around 70 per cent of what it was at this time of the ast year. So, the important reservoirs, 47 important reservoirs of the country, have only 70 per cent of water compared to the corresponding period of the last year. Particularly hard hit are the reservoirs of Ramganga, 25 per cent of the level of the last year; Pong Dam, 45 per cent; Tungabhadra, 52 per cent; Hirakud, 55 per cent; Koyna, 58 per cent and Rihand, 66 per cent.

So, Sir, this is the situation so far as our reservoirs are concerned.

So far as drinking water is concerned, there is also an acute problem. We have made plans for all these. Rajasthan, Gujarat, particularly Kutch, North Gujarat, part of Saurashtra, city of Ahmedabad, eastern parts of Vadodara and Baruch district, western and central Madhya Pradesh, parts of Haryana and western U.P. and Madras city continue to be bad so far as drinking water is concerned, urban and rural areas. The surface reservoir in all these areas are almost dry. There has been no appreciable recharge to the storage available prior to monsoon.

Therefore, Government of India has taken a number of steps, particularly the Rural Development Ministry under the stewardship of my friend, Shri Ramanand Yadav. They have already assessed the situation, planned for the future and are making all the arrangements for drinking water in the rural as well as the urban areas. They have planned for the use of the available surface water. They want to conserve it with the help of a catalytic alcohol by spreading it over the water. These are the steps which they have proposed:

- Development of the ground-water sources around urban areas.
- Requisition of private sources.
- Immediate stoppage of the overdrawal of ground water by irrigation pumps around urban conglomerates.
- Completion of a large number of water harnessing structures to tap the rainfall which may be available before September.

These are the steps the Rural Development Ministry has suggested. The Government of India is going to take these steps. Even today in the morning, the hon. Prime Minister held a meeting with the Committee on Drought and there was a detailed discussion about the prevailing situation. Suggestions were thrown by the Ministers and the Officers as to what should be done, how it should be planned, how we should prevent the loss to our cattle wealth, to the human beings and to our crop as well. So, the priorities are also fixed by the Government of India. We are fixing priorities as to what should be our first priority, what should be our second priority and what should be our third priority. That is what the Government of India is doing; that is what our Prime Minister is thinking and that is what we are planning.

Coming to the help and the amount to be given to the State Governments, during the Sixth Plan period Rs. 1,373.36 crores was spent for drought. It was the Central assistance ceiling sanctioned to the State Governments. Compared to this figure of the entire Sixth Plan period, during the two years and four months of the Seventh Five-Year Plan, we have already sanctioned a ceiling of Rs. 1,303.58 crores which is equal to the amount spent during the Sixth Plan period. Now, how can the hon. Members say that the Government of India is blind to the requirements of the State Governments? Is it the responsibility of the Government of India alone? The Eighth Finance Commission has said that it is a State subject and it is the duty of the State Government to meet the situation. But at the same time looking to the financial conditions of the State Governments and constraints on their resources, it has been decided that the Government of India should extend all help to the State Governments to supplement their efforts, to help them in their hour of crisis. That is why the amount given during these two years and four months period is just equivalent to the amount given during the Sixth Plan period. For other calamities like floods, cyclones etc., during the Sixth Plan Rs. 1,410.61 crores was given. As against that during these two years four months period it is Rs. 1,021.93 crores. If we analyse these two figures, we can understand as to what extent the Government of India has helped the State Governmens and how it is trying to help the State Governments Even if we look to the margin money which was earlier nearly Rs. 100 crores, it is now more than Rs. 240 crores. I can give you the exact figures. It is more than Rs. 240 crores as against Rs. 100 crores. It is much more than double the amount. I can give the figures of the damages but I do not want to take much of your time because all hon. Memebrs have given it. Sir, the margin money was Rs. 100.55 crores during the Seventh Finance Commission. It was raised to Rs. 240.75 crores by the Eighth Finance Commission. So it is more than double the amount. This amount is meant for meeting the immediate needs of the State Governments. As soon as they spend their margin money, they request for the ways and means advance from the Government of India and we have given in a number of cases and we are giving it. Sir, in 1984-85, 167 districts were affected. In 1985-86, 260 districts were affected. Now during 1987-88 it is much more because I have mentioned just now as to how many districts have received scanty rainfall.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Only 1/4th of the districts in the country received rainfall and 3/4th of the districts either received scanty or no rainfall at all.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Yes, I have given the figures of the Sixth Plan period.

श्री राम चन्द्र विकल : मंत्री जी मैंने यह जानना चाहा था कि इस वक्त क्या मदद दे रहे हैं, आप तो जनरल आंकड़े पुरानी योजनाओं के दे रहे हैं, लेकिन तत्काल जो समस्या है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, गोआ में, कर्नाटक में, केरल में, प० बी० में जो भयावह स्थिति है, उसमें आपने क्या मदद दी है राज्यवार बताएं? सदन यह जानना चाहता है कि राज्यवार इस वक्त क्या मदद दे रहे हैं या मदद देने का इरादा है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : विकल जी, आप जरा ठहरिए उनको बताने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सदन ने यह भी कहा है, कुछ तो बात कही है तो मुझ में कुछ तो बात कही पड़ती, बेकार उड़ने में तो नहीं आता हूं, आप बैठ रहिए, सुनते रहिए, आपको वह सब फिगर मिलेगा।

I will give the figures to the hon. Members. There is nothing wrong in asking for the figures. I am well equipped with the facts and figures of the situation and can give these to the hon. Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What are your future plans?

SSHRI YOGENDRA MAKWANA: I am comming to that But you see, Sir, I have to put the record straight. There are a number of hon. Members who have said nothing is done by the Government of India and nothing is given by the Government of India. How can I allow it to go on record? (*Interruptions*) I will give all the facts and figures to the hon. Members of this House and through this House to the country at large.

During the preceding three years, we have given Rs. 467.81 crores to 21 State Governments in 1985-86. In 1986-87, Rs. 609.34 crores were given. During 1987-88, Rs. 226.43 crores have been given. Even now I have received requests from various State Governments. Some hon. Members have said that the Government of Uttar Pradesh have requested for Rs. 100 crores. But so far I have not received the memorandum from them. I have received only a letter from the Chief Minister of Uttar Pradesh for Rs. 50 crores. Perhaps request for Rs. 100 crores may be on the way and I will be receiving it at any time. Pondicherry has requested for Rs. 0.42 crore. Tamil Nadu has requested for Rs. 52.71 crores. Gujarat has requested an ad hoc amount of Rs. 50 crores as a ways and means advance. Orissa, Rs. 60.53 crores and in respect of U.P., as I said, the Chief Minister has written a letter for Rs. 50 crores. So far as floods are concerned, Jammu and Kashmir has requested for Rs. 100.31 crores Assam Rs. 139.60 crores and Sikkim, Rs. 13.57 crores.

(*Interruptions*)

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: What about Maharashtra?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: All these State Governments, they are preparing their memoranda and for this purpose, they have to collect data and once they collect it, then alone, they will submit their memoranda and they know the situation. They request for ad hoc amount. They come before us. Earlier, the memoranda were also with us. So, these are the recent memoranda which are received and they are under process. There are a number of States who have requested for foodgrains also and we have given 55 thousand tonnes to Maharashtra, 1,18,750 tonnes to Madhya Pradesh, 3+2 that is 5 lakh tonnes to Rajasthan and 2 lakh tonnes to Gujarat. This is the quantity of foodgrains we have given to the State Governments. Sir, in spite of all this, we know that the situation is very bad and if you want, I can give the figures of the other programmes which my Ministry and other Ministeries are undertaking like the ARWSP, DDP, DPAP and RLEGP, NREP, all these figures are available with me but I do not want to take the time of the House by giving these figures to the House because I have given these figures earlier also. The main thing required to be done in this hour of crisis is to plan and we have made contingent plans for all, for everything.

So far as rice is concerned which is the major crop of the *kharif* season, the position in main rice growing States is satisfactory or average except in States of U. P., Assam and Tamil Nadu. Haryana and Punjab are also accepted because they also partly cultivate rice. In coarse grains, the position of jawar, maize, ragi and other millets is satisfactory or average in most of the major growing States. However, bajra crop is likely to suffer the most because the areas are Gujarat, Rajasthan and Haryana. There are the major States growing bajra. Therefore, bajra is the worst affected crop. In pulses, the position is satisfactory in eastern and north-eastern States and unsatisfactory in U.P. Rajasthan and Karnataka. This is the crop positon.

So far as fodder is concerned, we have arrangements for producing fodder from forest department by establishing fodder banks, procuring foodgrains unfit for human consumption from FCI, controlling supplly of straw for industrial purposes for diverting them for livestock feeding, augmenting production of Molases bricks to serve as drought feed supplement, procurement of bagasse from sugar factories for feeding purposes and establishment of cattle sheds. After this *kharif*, there will be the *rabi* season. We have to plan for that season also. It all depends upon the moisture content in the soil. So we have to plan for that also making the most cost effective use of irrigation during this *kharif* and saving the maximum quantity of water for *rabi*. There are crops which require a lot of water and there are crops which require less water. Therefore, we have to plan and economise on the availability of irrigation water. We have to optimise the available moisture by better management to increase productivity. In eastern States where there is good rain—parts of Assam, Orissa and West Bengal—we can utilise it for *rabi* crop. We should not grow water-exausting crope like paddy but should take up crops like maize, oilseeds, thuria, sun-flower and pulses. This is the planning we have done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What about drinking water?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The Rural Development Ministry has taken a number of measures. In the beginning I gave you the steps which were taken by the Rural Development Ministry.

SHRI GHAN SHYAM SINGH: What are the special measures taken?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: These are special measures. Nothing is a normal measure now, in a situation like this. At normal times, I do not think the Rural Development Ministry has planned like this. There are measures for diverting water underground and in reservoirs, which are used for irrigation purposes, to drinking purpose. That is one of the steps we have taken. There are also measures for preservation of the available water. Now, avaporation is very high. At normal times, the evaporation, I am told by the scientists, is one inch a day. Now it is five inches a day. That is why they have to spray some chemical on it so that the evaporation loss can be reduced. Then, the development of ground water resources. This, I have narration, I am told by the scientists, is one have taken a number of steps and we are planning for a number of steps to be taken.

The main areas, which are the areas of anxiety, where we have to plan are:—

1. Agriculture
2. Employment generation
3. Food for the people
4. Drinking water and
5. Fodder for the animals.

These are the five critical areas.

I just informed the hon. Members about the action taken on drinking water, fodder for the animals and food.

So far as agriculture is concerned, as rightly pointed out by one of the hon. Members, we have to provide electricity to our farmers. Instructions are given to the State Governments that electricity should be diverted from industry to agricultural sector. The State Governments of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh have already passed the instructions. They have diverted electricity from industry to agriculture. Adequate diesel should also be given to them so that they can run their pumps to lift sub-soil water. For that that also we have made provision. Even today, in the morning, the Prime Minister called the Secretary, Petroleum Department, and told him that all the diesel should be diverted for agricultural purposes first. They should take all the necessary precaution to ensure that diesel is made available to our farmers.

[Shri Yogendra Makwana]

So far as employment generation is concerned, the Government of India has provided relief assistance to the State Governments, food to the State Goverament, so that they can generate more employment for the people who are supposed to be engaged in agriculture but not so engaged how because there is no rain. For that, this employment generation is the major programme that the Government of India has taken up.

One honourable Member, Mr. Satya Pal Malik—he is not here—asked at what point of time the Government of India started taking acton and at what point of time they thought about the situation. He is not here, but I would like to tell the honourable Members present here that we started planning right from April 1987. Monsoon sets in mid-May but we started planning in April 1987, well before the onset of monsoon, with a *kharif* conference of the State Government. A *kharif* conference was held here in Delhi and we gave necessary instructions for positioning of seeds, fertilizers, pesticides, etc. and made arrangements for water and other things. Everything was discussed in this kharif conference and arrangements were made. We set up a Weather Study Group in my Ministry with IMD—Indian Meteorological Department—the Ministry of Water Resources, the Ministry of Agriculture and the Indian Council of Agricultural Research as members. This group was initially meeting every week. Now they meet every third day in Krishi Bhavan and make an assessment of the rainfall and monsoon situation. They prepare a contingency crop plan including mid-course corrections on crop plans to suit aberrant weather conditions and inform States to take suitable steps for their requirements of seeds. On 29th June 1987 we had a meeting of Relief Commissioners of States to discuss the delayed monsoon and to plan for future contingencies. Finally we discussed in detail the contingency plans made for each State in the Agricultural Production Commissioners' Conference on 28th July 198. We also set up a task force consisting of representatives from the Department of Agriculture, the Water Resources Ministry and the Indian Meteorological Department, for monitoring the utilisation of the available irrigation potential—major, medium and minor—in the country so as to ensure economy in the use of water for kharif and rabi crops and to plan for meeting the seed requirements of the next kharif, viz. 1988-89, because we require seeds. Then we have a Crisis Management Group. Somebody today asked why we should not have a committee which can take the work on a war footing. This is that committee—the Crisis Management Group or you can call it the War Footing Committee, if you like— consisting of senior officers of the Department of Agriculture and Cooperation, the Department of Rural Development, the Ministry of Forest and the Indian Meteorological Department for attending to the daily problems faced by State Governments in providing relief. Over and above this, we have contingency plans for all the States. I have all the contingency plans for all the States with me which we have sent to the State Governments and which are monitored by different groups which are set up in my Ministry who everyday meet and decide about it.

These are the measures which the Government of India has taken. Our Prime Minister is very much concerned about it. He has instructed the Ministry that all our resources, all our technical manpower and all our scientists should be devoted for helping the farmers of this country in this hour of crisis. We are in constant touch with the State Governments and whenever they require any type of help, we are there and we are helping them. This is the action which the Government, the Ministry of Agriculture, has taken to meet the situation arising out of the delayed and aberrant monsoon. Thank you very much.